लोकतंत्र के आयाम

लोकतंत्र के आयाम

SCHOOL FOR DEMOCRACY SFD
लोकतंत्र शाला

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष

द्वारा प्रकाशित:
कल्पवृक्ष, अपार्टमेंट- ५ श्री दत्त कृपा,
९०८ डेक्कन जिमखाना, पुणे ४११००४
http://www.kalpavriksh.org/
http://www.vikalpsangam.org/

तथा
लोकतंत्र शाला, गाँव-बडी का बाड़ीया, पोस्ट- थाणा, ज़िल्हा-भीलवाड़ा, राजस्थान- ३११ ८०४
www.schoolfordemocracy.org

द्वारा समर्थित:
हेनरिक बोएल स्टिफ्टुंग - भारत
https://in.boell.org/en/homepage

वर्ष
२०१९

पाठ:
यह लेख निम्न पुस्तक से लिये गये हैं:

'**प्लूरीवर्स:** एक उत्तर-विकासवादी शब्दकोश' (Pluriverse: A Post-Development Dictionary)

संपादक: अशीष कोठारी, अरियल सलेह, अर्तुरो एस्कोबार, फेडेरिको डेमारिअ, अल्बेर्टो अकोस्ता

प्रकाशक: तुलिका व औथर्स अपफ्रन्ट, नइ दिल्ली.

द्वारा अनुवाद:
अमित शर्मा (मज़दूर किसान शक्ति संगठन)

मुखपृष्ठ तस्वीर:
नर्मदा बचाओ आंदोलन का तीसवा सालगिरा, बडवानी, मध्य प्रदेश, भारत
द्वारा: अशीष कोठारी

द्वारा डिजाइन और मुद्रित:
मुद्रा, ३८३, नारायण पेठ, पुणे

इस कार्य को क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस एट्रीब्यूशन-नॉन कमर्शियल-शेयरएलाइंट ४.० इन-इंटरनेशनल (cc BY-NC-SA 4.0) के तहत लाइसेंस प्राप्त है।

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

आप गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सामग्रियों की प्रतिलिपि बनाने, पुनर्वितरित करने और उन्हें अनुकूलित करने के लिए स्वतंत्र हैं अगर आप सुनिश्चित करें कि मूल लेखकों और फ़ोटोग्राफ़रों के लिए जिम्मेदारियों के साथ, स्पष्ट रूप से बदले हुए भागों और एक समान लाइसेंस के तहत संकेत दिए गए हैं ।

तालिका पृष्ठ

परिचय

१. **मूलभूत पारिस्थितिकीय लोकतंत्र**-*अशीष कोठारी* १

२. **ज़ापातीस्ता स्वायत्तता** *सोचील-लेवा-सोलानो* ४

३. **प्रत्यक्ष लोकतंत्र**-*क्रिस्टोस ज़ोग्राफोस* ७

४. **प्राकृतिक स्वराज**-*असीम श्रीवास्तव* १०

५. **क्रांति**-*एदुआर्दो गुडिनास* १३

६. **ईको-समाजवाद**-*माइकल लोवी* १६

७. **सामाजिक पारिस्थितिकी**-*ब्रायन टोकर* १९

८. **स्वायत्तता**-*गुस्तावो एस्तेवा* २२

९. **कुर्दिस्तान की लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था**-*अज़ीज़ असलान और बेंगी अक़बूलत* २५

१०. **ईको-अराजकतावाद**-*टेड ट्रेनर* २८

लोकतंत्र के आयाम

इस संकलन की एक संक्षिप्त भूमिका

यह दस निबंध जो कि मूलत: 'प्लूरीवर्स: एक उत्तर-विकासवादी शब्दकोश' (Pluriverse:A Post-Development Dictionary) नामक पुस्तक से लिए गए हैं, लोकतंत्र के उन विविध पहलुओं को दिखाते हैं जिस तरह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोकतंत्र को बरता जाता है और इसके बारे में सोचा जाता है। इन सभी उदाहरणों में लोकतंत्र (democracy) के असल अर्थ (demos=जनता;cracy=शासन) यानी जनता द्वारा शासन को जीवंत किया गया है।

पिछले लम्बे समय से ऐसे 'उदार लोकतंत्र' (liberal democracies) बहुत आम हो चले हैं जिनमें सत्ता-शक्ति लोगों में निहित ना होकर दर-असल उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में निहित होती है। हालाँकि ऐसे तंत्र तानाशाही या फ़ासिवादी सरकारों से निश्चित तौर पर बेहतर हैं लेक़िन अधिकतर ये फिर भी लोकतंत्र के असल मतलब से बहुत दूर हैं। इनमें से कुछ में, जैसे उन देशों में जहाँ शासन का झुकाव कुछ हद तक दक्षिणपंथी है और जहाँ लोकतंत्र और तानाशाही (या कुछ लोग जिसे फ़ासिवाद भी कहेंगे) के बीच जो बहुत साफ़ फ़र्क़ होना चाहिए वह बहुत धुँधला होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जहाँ वाम-पंथी दल सत्ता में रहे हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से, ग्रीस आदि, वहाँ भी आदिवासियों और स्थानीय समुदायों तथा पर्यावरण सम्बंधी हक़ों पर गहरे प्रहार किए गए हैं और दोहन-आधारित, आर्थिक वृद्धि के पीछे भागने वाली अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावी रूप से शक्ति का विकेंद्रीकरण करने में आड़े आ रही हैं।

यह निबंध तानाशाही और उदार, केंद्रिकृत लोकतंत्र दोनों के बनिस्बत मूलभूत विकल्प पेश करते हैं। इनमें कुछ ज़मीनी पहलें हैं जो बहुत छोटी (स्थानीय) तो कुछ काफ़ी बड़े स्तर की हैं जैसे भारत और लैटिन अमेरिका में मूलवासियों के स्वराज के प्रयास, मेक्सिको में जापतिस्ता और चिआपास और केंद्रीय एशिया में कुर्दिश स्वायत्त क्षेत्र; साथ ही (व्यावहारिक पहलों से जुड़ी हुई) सैद्धांतिक और दूरगामी धारणाएँ जैसे मूलभूत लोकतंत्र (radical democracy), स्वराज, ईको-समाजवाद, ईको-अराजकतावाद आदि भी शामिल हैं।

स्वायत्तता और क्रांति पर निबंध इस बात पर ज़ोर डालते हैं कि इन विचारों को सिर्फ़ प्रगतिशील दलों द्वारा सत्ता पर क़ाबिज़ होने तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि राज्य-सत्ता को ही नए सिरे से देखने की शुरुआत करनी होगी। साथ ही पश्चिमी, औपनिवेशिक और आधुनिकता की उन अवधारणाओं को भी फिर से परखना होगा जो राष्ट्र-राज्य और उदार लोकतंत्र के विचारों के मूल में हैं। राष्ट्र-राज्य के परे जाते हुए राजनैतिक सरहदों को पारिस्थितिकी-क्षेत्रीय (eco-regional) और जैव-सांस्कृतिक (bio-cultural) नज़रियों से देखना एक अहम दीर्घ-कालिक लक्ष्य बन जाता है। खुले स्थानीयकरण पर निबंध मूलभूत लोकतंत्र और आर्थिक जनतंत्रीकरण के बीच अहम रिश्ते को रेखांकित करता है। साथ ही इन निबंधों के ज़रिए पारिस्थितिकीय समझदारी, लचीलेपन और सततता (sustainability) की बुनियादी अहमियत पर ज़ोर दिया गया है।

'प्लूरीवर्स : एक उत्तर-विकासवादी शब्दकोश' (Pluriverse: A Post-Development Dictionary) के इन निबंधों को हम यहाँ इस विचार के साथ पेश कर रहे हैं कि हमारे देशों और इलाक़ों में लोकतंत्र को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए इस विषय पर चल रहे विमर्श में अपना योगदान दे सकें।

मूलभूत पारिस्थितिकीय लोकतंत्र (Radical Ecological Democracy)

अशीष कोठारी Ashish Kothari

प्रमुख शब्द: विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण, समुदाय, ईको-स्वराज

पूरी दुनिया में हो रहे पारिस्थितिकीय विनाश और सामाजिक-आर्थिक अन्याय के बीच बहुत सी ऐसी पहलें भी बढ़ रही हैं जो मानव की भलाई और खुशहाली पाने के ऐसे रास्तों पर चल रही हैं या उनके बारे में सोचने की कोशिश कर रही हैं जो सतत और न्यायपूर्ण हों। इनमें से कुछ पहले से चली आ रही जीवन-पद्यतियों और आजीविका के तरीक़ों पर आधारित हैं जो शताब्दियों या सहस्त्राब्दियों से धरती के साथ बेहतर सामंजस्य बना कर चल रही थीं। और दूसरी कुछ नई पहलें हैं जो प्रतिरोध आंदोलनों से उपजी हैं या वर्तमान में प्रभावशाली राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की विनाशक प्रकृती का सामना करने से उपजी हैं। हालाँकि ये पहलें और दृष्टिकोण अपनी प्रक्रियाओं और पृष्ठभूमि में बहुत अलग-अलग हैं लेकिन इनमें कुछ एक जैसी विशेषताएँ भी हैं जो व्यापक ढाँचों या प्रतिमानों को बनाना मुमक़िन करती हैं।

इनमें से एक ऐसा ढाँचा जो ज़मीनी तजुर्बों से निकला है लेकिन जो अब विश्व-भर में अपनाया जा रहा है वह है-मूलभूत पारिस्थितिकीय लोकतंत्र (RED) जिसे स्थानीय तौर पर 'ईको-स्वराज'[१] भी कहा जाता है। यह एक ऐसी धारणा है जो धरती की सीमाओं (limitations) और सिर्फ़ मानव ही नहीं बल्कि अन्य सभी प्रजातियों के हक़ों का सम्मान करती है और सामाजिक न्याय और निष्पक्षता जैसे मूल्यों की ओर बढ़ने की कोशिश करती है। यह धारणा लोकतांत्रिक और समानतावादी ऊर्जा से हर एक इंसान को इतना मज़बूत बनाना चाहती है ताकि वह निर्णय-प्रक्रिया का हिस्सा बन सके और मानव की भलाई और खुशहाली की इसकी सोच में शारीरिक, भौतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक आयाम भी शामिल हैं[२]।

स्वराज की यह अवधारणा राज्य या कम्पनियों को नहीं बल्कि जन-समूहों और समुदायों को प्रशासन और अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखती है। यह धारणा भारतीय उप-महाद्वीप में शुरू की गयी वास्तविक-जीवन की कई पहलों पर आधारित है जिनमें सतत खेती, मछली-पालन और पशु-पालन, भोजन और पानी के मामले में संप्रभु होना, विकेंद्रिकृत ऊर्जा उत्पादन, प्रत्यक्ष स्थानीय स्वशासन, सामुदायिक स्वास्थ्य, वैकल्पिक शिक्षण और अध्ययन, समुदाय-नियंत्रित मीडिया और संचार, अर्थव्यवस्थाओं का स्थानीय-करण, लिंग और जाति के मामले में न्याय, विशेष-योग्य जनों और कई तरह के यौनिक रुझान वाले लोगों के हक़ आदि शामिल हैं।[३]

मूलभूत पारिस्थितिकीय लोकतंत्र के निम्न पाँच भाग हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं:

१) पारिस्थितिकीय समझदारी और लचीलापन: इसमें प्रकृति का संरक्षण और बाक़ी क़ुदरत-पारिस्थितिकी-तंत्र, प्रजातियाँ, प्रकार्य (functions), चक्र, आदि. तथा इनकी जटिलता और पुनर्जीवन की क्षमता भी शामिल है। यह इस विचार पर आधारित है कि मानव भी क़ुदरत का हिस्सा हैं और बाक़ी क़ुदरत (ग़ैर-मानव) को भी फलने-फूलने का मूलभूत हक़ है।

२) सामाजिक बेहतरी और न्याय: इसके मायने यह हैं कि लोगों का जीवन संतोषप्रद और संतुष्टि-कर हो शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर; सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक हक़/लाभ और ज़िम्मेदारियाँ सभी को (लिंग, वर्ग, जाति, उम्र, नस्ल, विभिन्न शारीरिक/मानसिक अबलता या सबलता, लैंगिक रुझान या किन्हीं अन्य मौजूदा विभाजनों के बिना) निष्पक्ष रूप से मिलें। जहाँ सामूहिक हितों और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक संतुलन हो और जहाँ शांति और सद्भाव सुनिश्चित किए जाएँ।

३) प्रत्यक्ष या रैडिकल राजनीतिक लोकतंत्र: जहाँ निर्णय लेने की शक्ति मानव बस्तियों (चाहे शहरी हों या ग्रामीण) की सबसे छोटी इकाई के पास हो और हर इंसान के पास इसमें भाग लेने का हक़, क्षमता और अवसर हो। इन्हीं आधारभूत इकाइयों से शुरू करते हुए बड़े स्तर के शासन के ढाँचे हों जो अपने से नीचे की

इकाइयों के प्रति जवाबदेह हों। जहाँ राजनीतिक निर्णय पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक जुड़ाव और सीमाओं का सम्मान करते हुए लिए जाएँ। इसका मतलब है कि वर्तमान राजनैतिक सरहदों (जिसमें राष्ट्र-राज्यों/nation-states की सरहदें भी शामिल हैं) को चुनौती दी जाए। और जहाँ अंतत: राज्य की भूमिका नगण्य हो जाए जैसे सिर्फ़ उन कामों के लिए जहाँ बड़े भू-क्षेत्रों में आपस में समन्वयन की ज़रूरत हो और या फिर जो भी ज़रूरी कल्याणकारी प्रयास हों उनके लिए।

४) आर्थिक लोकतंत्र: इससे अभिप्राय ऐसे लोकतंत्र से है जहाँ स्थानीय समुदाय (जिनमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को जोड़ कर 'Prosumer' कहा जा सकता है) उत्पादन के साधनों, वितरण, विनिमय और बाज़ारों पर नियंत्रण रखते हों। जहाँ स्थानीय-करण स्थानीय क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के द्वारा बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक अहम सिद्धांत हो। व्यापक व्यापार और विनिमय ज़रूरत के मुताबिक़ स्थानीय आत्म-निर्भरता को बचाए रखे। प्रकृति, प्राकृतिक संसाधन और अन्य ज़रूरी तत्व जो अर्थव्यवस्था में खपते हैं उन्हें शामलात (लोक-सम्पत्ति) के तौर पर शासित किया जाए। निजी सम्पत्ति को बहुत कम या पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। जहाँ समाज में एक-दूसरे की देखभाल और मिल-बाँट कर जीने के ग़ैर-मौद्रिक रिश्तों को फिर से केंद्रीय स्थान मिले। सामाजिक खुशहाली के सूचक अधिकतर गुणात्मक हों और उनके केंद्र में बुनियादी ज़रूरतें और सबकी भलाई हो।

५) ज्ञान और संस्कृति की बहुलता: ऐसे लोकतंत्र में विविधता एक अहम सिद्धांत होता है। ज्ञान (इसका उद्‌भव, उपयोग और संचार) सार्वजनिक या लोक-सम्पत्ति के रूप में हो। नव-प्रवर्तन लोकतांत्रिक तरीक़े से उपजें और जहाँ 'विशेषज्ञता' के ढाँचे ना हों। सीखना-सिखाना जीवन के हिस्से की तरह हो ना कि किन्हीं 'विशेष' संस्थानों तक ही सीमित हो। नैतिक और आध्यात्मिक भलाई के व्यक्तिगत और सामूहिक रास्ते सभी के लिए उपलब्ध हों।

इसे एक फूल की पंखुड़ियों की तरह देखा जाए तो तना या कली जिससे ये पंखुडियां निकलती हैं वे निम्न मूल्यों या सिद्धांतों से बने हों (और ये सिद्धांत भी वैकल्पिक प्रयासों के अहम हिस्से के तौर पर उभरें)। इन्हें समाजों की नैतिक या आध्यात्मिक बुनियादों के तौर पर भी देखा जा सकता है यानी समाज के सदस्यों की जीवन-दृष्टि में ये शामिल हों:

- पारिस्थितिकीय अखंडता (integrity) और क़ुदरत के हक़
- निष्पक्षता, इंसाफ़ और समावेश
- सार्थक भागीदारी का हक़ और ज़िम्मेदारी
- विविधता और बहुलता-वाद
- व्यक्तिगत आज़ादियों के प्रति एकजुटता और सामूहिक लोक-सम्पत्तियाँ
- लचीलापन और अनुकूलन (adaptability)
- Subsidiarity (सब्सिडीएरिटी), आत्म-निर्भरता और ईको-क्षेत्रवाद
- सादगी और पर्याप्तता ('पर्याप्तता' की संकल्पना)
- मज़दूरी और काम-काज में रचनात्मकता और गरिमा
- अहिंसा, सद्‌भाव और शांति।

'ईको-स्वराज'के विस्तृत मूल्य और घटकों पर पूरे भारत में 'विकल्प संगम' नामक प्रक्रिया के तहत चर्चा चल रही है[४]। यह प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों, समुदायों और नागरिक संस्थानों और अलग-अलग व्यवसायों में विकल्पों पर काम कर रहे लोगों को साथ लाने का काम करती है। क्षेत्रीय और अलग-अलग प्रसंगों पर 'संगमों' की २०१५ में शुरू हुई यह ऋंखला प्रतिभागियों को अपने अनुभव बाँटने, एक-दूसरे से सीखने, सहयोग करने, गठबंधन बनाने और साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य का खाक़ा खींचने में मदद करती है। कहानियों, विडीओ, केस-स्टडी और अन्य तरीक़ों से इन विकल्पों का दस्तावेजीकरण होने से इसे अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने और बदलाव के लिए प्रेरणा देने में मदद मिली है और इस सब के लिए एक समर्पित वेब-साइट, चलत-प्रदर्शनियाँ और अन्य तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया है।

भारत के परे यह धारणा दुनिया के दूसरे हिस्सों के मूलभूत विकल्पों को भी साथ जोड़ रही है। २०१२ में बहुत-सी नागरिक समाज संस्थाओं और आंदोलनों ने एक 'मूलभूत पारिस्थितिकीय लोकतंत्र और सततता पर एक जन-संधि'[६] पर हस्ताक्षर किए। और इसके बाद एक चर्चा सूची की मदद से संवाद बनाए रखने और अहम विषयों/धारणाओं के ज़रिए एक-दूसरे से सीखने के अवसर खोजे गए हैं जैसे-अ-विकास (degrowth), ईको-नारीवाद, सहकारी संस्थाएँ, यूरोप में सामाजिक/एकजुटता अर्थ-

व्यवस्था (solidarity economy) और दक्षिण अमेरिका के buen vivir और अन्य जगहों पर इसकी समकक्ष व्यवस्थाएँ आदि।

ईको-स्वराज[६] RED एक विकसित होती हुई जीवन-दृष्टि है कोई तयशुदा ख़ाका नहीं। इसकी लोकतांत्रिक और ज़मीन से उपजने वाली प्रक्रिया ही ऐसी है कि जो ऊपर-से-नीचे थोपी जाने वाली विचारधाराओं और संकल्पनाओं का एक विकल्प तैयार करती है और साथ में इन विचारधाराओं के प्रासंगिक तत्वों को भी साथ लेकर चलती है। बदलाव/रूपांतरण की इसकी (अभी तक अविकसित) क्षमता का यही आधार है।

नोट:

१ स्वराज के अर्थ के लिए इसी पुस्तक के निबंध 'प्राकृतिक स्वराज' को देखें।

२ देखें Kothari 2014; Shrivastava and Kothari 2012.

३ सैकड़ों उदाहरणों के लिए देखें - www.alternativesindia.org

४ इसकी प्रक्रियाओं और परिणामों की जानकारी यहाँ उपलब्ध है. http://kalpavriksh.org/index.php/alternatives/alternatives-knowledgecenter/353-vikalpsangam-coverage.

५ विकल्प संगम, www-vikalpsangam.org

६ मूलभूत पारिस्थितिकीय लोकतंत्र, http://radicalecologicaldemocracy.wordpress.com.

अन्य संसाधन:

Kalpavriksh Environment Action Group, http://kalpavriksh.org/index.php/alternatives/alternatives-knowledge-center/353-vikalpsangam-coverage.

Kothari, Ashish (2014), 'Radical Ecological Democracy: A Way for India and Beyond', Development, 57 (1): 36–45.

Shrivastava Aseem and Ashish Kothari (2012), Churning the Earth: The Making of Global India. New Delhi: Viking/Penguin India.

लेखक परिचय:

अशीष कोठारी भारतीय पर्यावरणीय समूह 'कल्पवृक्ष' के संस्थापकों में से एक हैं। वे लोक प्रशासन के भारतीय संस्थान (IIPA) में अध्यापन कर चुके हैं और भारत की राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति और एक्शन प्लान का समन्वयन भी कर चुके हैं। वे ग्रीन पीस इंडिया और ग्रीन पीस इंटर्नेशनल के बोर्ड सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने वैश्विक ICCA Consortium की शुरुआत करने में मदद की है, साथ ही वे IUCN के संरक्षित क्षेत्रों और समुदायों के नेट्वर्क की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। अशीष ने तीस से भी ज़्यादा किताबों का सह-सम्पादन और सह-लेखन किया है जिनमें Birds in Our Lives (Churning the Earth (and Alternative Futures: India Unshackled आदि शामिल हैं। वे 'विकल्प संगम' और Global Confluence of Alternatives Processes का समन्वयन करने में मदद करते हैं और रोज़ा लगज़ेमबर्ग फ़ाउंडेशन द्वारा स्थापित Permanent Group on Alternatives to Development के सदस्य भी हैं।

ज़ापातीस्ता स्वायत्तता
(Zapatista Autonomy)

सोचील लेवा–सोलानो Xochitl Leyva-Solano

प्रमुख शब्द: Zapatismo, स्वायत्त प्रथाएँ, सु-शासन, पूँजीवाद-विरोधी संघर्ष

ज़ापातीस्ता आंदोलन की प्रतिरोध और विद्रोह की प्रथाओं में 'ज़ापातीस्ता स्वायत्तता' एक केंद्रीय तत्व है। इसमें वे सभी पद्धतियाँ, प्रक्रियाएँ तथा संघर्ष, सरकार और विद्रोही जीवन के तंत्र शामिल हैं जो मिलकर स्थापित व्यवस्थाओं और इसके संस्थानों का एक रैडिकल विकल्प पेश करते हैं। ज़ापातीस्ता स्वायत्तता (आज़ादी) समाज के निचले तबक़ों और वाम-विचारों से प्रभावित लोगों से उभरती है। इसके कई आयाम हैं।

प्रतिरोध के रूप में: राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए ज़ापातीस्ता आर्मी (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) के लम्बे प्रतिरोध को १ जनवरी, १९९४ के First Declaration of the Lacandon Forest में कुछ यूँ बताया गया है: ''हम ५०० साल के संघर्ष का परिणाम हैं।'' इसके बाद, EZLN ने सरकार पर युद्ध की घोषणा कर दी और मेक्सिकन लोगों को श्रम, भूमि, आवास, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आज़ादी, लोकतंत्र, न्याय और शांति हासिल करने के इस संघर्ष से जुड़ने का आह्वान किया। १९९४ में EZLN ने अड़तीस विद्रोही नगरपालिकाएँ बनाने की घोषणा भी की और इस तरह सेना का घेरा तोड़ा और सरकार द्वारा लागू विद्रोही-विरोधी रणनीति का सामना किया।

गरिमा, सुशासन तथा विद्रोह: अपने शुरुआती कामों के लिए EZLN को मेक्सिकन संविधान के अनुच्छेद ३९ का बल भी मिला जो यह स्थापित करता है कि ''लोगों को, हमेशा, यह अहरणीय अधिकार है कि वे अपनी सरकार के प्रकार में सुधार करे या उसे बदल दें।'' जब सरकार ने EZLN के साथ १९९६ में हस्ताक्षर-युक्त San Andres करार की शर्तों को पूरा नहीं किया तो इस अनुच्छेद की ओर अपील को और बल मिला। इन समझौतों का आदर करते हुए सरकार ने नया संवैधानिक ढाँचा बनाने की ओर क़दम नहीं बढ़ाए जो हर स्तर पर और हर क्षेत्र में मूलनिवासियों द्वारा स्व-शासन और स्वायत्तता को मुमकिन बनाते। एक लम्बे युद्ध का सामना करते हुए जिसमें बार-बार उन पर हमला कर उन्हें कमज़ोर करने की कोशिशें हुईं, ज़ापातीस्ता आंदोलन ने लोगों की बस्तियों से निकले स्वशासी सरकार चलाने की प्रथाओं और नेट्वर्क को आपस में जोड़ा जिसकी परिणिति ज़ापातीस्ता विद्रोही और स्वशासी नगरपालिकाओं (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas] MAREZ), और ज़ापातीस्ता रीजन (region) और ज़ोंस (zones) में हुई। इन सभी को 'आज्ञा-पालन से शासन' (governing by obeying) के सिद्धांत के तहत संचालित किया गया, और इसके कुछ बुनियादी आधार थे:

- सेवा करना ना कि सेवा करवाना
- प्रतिनिधित्व करना ना कि जग़ह लेना
- निर्माण करना, विध्वंस नहीं
- आज्ञा-पालन, ना कि निर्देशों की पूर्ति
- प्रस्तावित करना ना कि थोपना
- राज़ी करना ना कि हराना
- नीचे जाना, ऊपर नहीं

इन आधारों पर चलने से मेक्सिकन राजनैतिक व्यवस्था की 'ख़राब सरकारों' की ख़ामियाँ जैसे भ्रष्टाचार, हिंसा, दंड-अभाव आदि उजागर हुईं और इसने नैतिकता को राजनीति के केंद्र में ला दिया।

जब 'जनता आदेश देती है और सरकार उनकी आज्ञा मानती है' तो इससे सरकार और जनता दोनों ही के स्थायी 'अधिकार' और 'कर्तव्य' स्थापित हो जाते हैं। प्राधिकरणों का चुनाव अक़्सर जन-विधानसभाओं से होता है। अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग प्राधिकरण निम्न हैं: स्वशासी प्रतिनिधि और कमिसार (commissars); नगरपालिका और क्षेत्रीय स्वशासी परिषद के सदस्य; विभिन्न कार्य-क्षेत्रों के समन्वयक, विभिन्न आयोगों और गुड गवर्न्मेंट काउन्सिल (Juntas de Buen Gobierno, JBG) के सदस्य जो कि हर ज़ोन के स्तर पर काम करते हैं और Caracoles Zapatistas में होते हैं।

ज़ापातीस्ता स्वशासी सरकार को कार्य-क्षेत्रों के अनुसार संगठित किया जाता है जो वक़्त के साथ बदलते रहते हैं और हर नगरपालिका में अलग-अलग होते हैं लेकिन अधिकतर इनमें ये क्षेत्र शामिल होते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि-पारिस्थितिकी, महिलाएँ, कृषि से जुड़े मुद्दे, न्याय, संचार, वाणिज्य, यातायात, प्रशासन और दीवानी रजिस्ट्री। इन क्षेत्रों में और सरकार के अन्य स्तरों पर लोग रोटेशन (यानी बारी-बारी से) और सामूहिक तौर पर नियुक्त होते हैं और ये पद अवैतनिक होते हैं।

हर व्यक्ति जो इसमें हिस्सा लेता है वह अपने होने, काम करने, सीखने और 'unlearn' करने की क्षमता के आधार पर दूसरों से जुड़ा होता है। ऐसा करके वे सामाजिक संगठन के प्रभावी तरीक़ों को चुनौती देते हैं और व्यक्तिगत और विशेषीकृत श्रम मज़दूरी (specialized wage labour) पर आधारित शक्ति को भी।

एक रैडिकल, समग्र और जीवन-दायी विकल्प (life-creating alternative) के तौर पर: ज़ापातीस्ता को जो समर्थन ज़मीनी तौर पर मिलता है इसमें मूलवासी कैम्पेसीनोज़ (स्पैनिश में किसान) शामिल हैं जो अपनी जीविका और प्रजनन के लिए खेती करते हैं और इस तरह अपने स्वशासी संघर्षों के लिए भौतिक परिस्थितियाँ तैयार करते हैं। महिलाओं का स्थान भी अहम होता है ठीक वैसे ही जैसे जीवन-प्रदायी भूमि और धरती माता होती हैं। 'क्रांतिकारी महिला कानून' (Revolutionary Women's Law) ने महिलाओं के राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के साथ-साथ उनकी शारीरिक और नैतिक अखंडता पर ज़ोर देने और उनका ख़याल रख कर महिलाओं को भी क्रांतिकारी संघर्ष का हिस्सा बना लिया।

इस क़ानून में लिखी बातें बेमानी ही होतीं अग़र ज़मीनी स्तर पर महिलाएँ- EZLN की सशस्त्र महिलाओं के साथ संवाद क़ायम रखते हुए- इन संघर्षों को हर तरीक़े से अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनातीः चाहे वह ऑक्युपेशन की सेना के सम्बंध में हो, या स्वयं अपने हाथों से ज़मीन में फ़सल उगाना हो, खोई हुई भूमि को फिर से ठीक करना हो, या अपने बेटों-बेटियों को फिर से socialise करना हो, चाहे सहकारों को बनाना/संचालित करना हो, या स्वशासी शिक्षा के शिक्षक बनना हो या स्वशासी उपचार या रेडीओ या विडीओ बनाने के काम हों।

इसमें कोई शक़ नहीं कि ज़ापातीस्ता संघर्ष ज़मीनी स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच अपनी जड़ें क़ायम करने की वजह से ही बढ़ पाया। उनके सहयोग से ज़ापातीस्ता राजनीति वह ताक़त हासिल कर पाई जो कई अन्य क्रांतिकारी प्रयास नहीं कर पाए क्यूँकि वे अपने संघर्षों को रोज़मर्रा के जीवन से नहीं जोड़ पाए और महिलाओं, परिवारों, समुदायों, साधारण जीवन, समूह और ट्रान्स-नैशनैलिटी (राष्ट्र से परे) आदि सभी आयामों को साथ लेकर चल पाए।

वर्तमान में जारी (नीचे से ऊपर) वैश्वीकरण के एक केंद्रीय संदर्भ के तौर पर: Zapatista Intergalactic Encounter for Humanity and Against Neoliberalism के बीस साल बाद लिटल ज़ापातीस्ता स्कूल के एक युवा अभिभावक Alejandra ने ज़ापातीस्ता glocal planetary consciousness को संक्षेप में कुछ यूँ बताया, ''जैसा कि हम जानते हैं, पूँजीवादी व्यवस्था वही करती है जो वह चाहती है। वे तय करते हैं कि शासन कैसे चलेगा, हमें कैसे रहना चाहिए, और हम ऐसा नहीं चाहते..... हम सिर्फ़ अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं..... हम सभी के लिए आज़ादी चाहते हैं ज़ापातीस्ता के तौर पर हम हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं..... हम अपने शब्द, अपनी राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं.... हम इस (मौजूदा) व्यवस्था को हराना चाहते हैं यही हमारा मुख्य लक्ष्य है।''[१]

नोट:

१. यहाँ उपलब्ध है. Rebeldía Zapatista 1, 2014, p. 53.

अन्य संसाधन:

EZLN, http://enlacezapatista.ezln.org.mx.

——— (2013), Cuadernos de texto de primer grado del curso. Mexico: Escuelita Zapatista-EZLN.

——— (2014), Rebeldía Zapatista:La Palabra del EZLN,1 and 3, February and September: Mexico, http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/02/28/editorial-revista-rebeldia/.

——— (2016), Critical Thought in the Face of the Capitalist Hydra: I', Contributions by the Sixth Commission of the EZLN. Durham: Duke

University Press. Seminarios CIDECI-UniTierra Chiapas, http://seminarioscideci.org.

ProMedios de Comunicación Comunitaria, http://www.promediosmexico.org. Radio Zapatista, http://www.radiozapatista.org.

लेखक परिचय:

सोचील लेवा altermundista (वैकल्पिक-वैश्वीकरण) नामक समूह और नेटवर्क की सह-संस्थापक और कार्यकर्ता हैं। वे मेक्सिको के CIESAS Sureste (Chiapas) में शोध करती हैं और उन्होंने कई विडीओ और मल्टीमीडिया प्रोडक्ट भी तैयार किए हैं। साथ ही उन्होंने कई लेख और किताबें महिलाओं और युवा मूलवासियों के साथ लिखी हैं जो प्रतिरोध में संलग्न हैं। इन्हें ऐक्टिविस्ट, अकादमिक और सामुदायिक संदर्भों में काम में लिया जाता है।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Demoracy)

क्रिस्टोस ज़ोग्राफोस Christos Zografos

प्रमुख शब्द: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्व-शासन, स्वायत्तता, सामाजिक-पारिस्थितिकीय बदलाव

प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता द्वारा स्व-शासन की वह पद्धति है जिसमें नागरिक सीधे, लगातार और बिना किसी मध्यस्थता के सरकार के काम-काज में भाग लेते हैं। यह लोकतंत्र का एक रैडिकल स्वरूप है जो विकेंद्रीकरण और शक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा वितरण का पक्षधर है जिससे शासक और शासित के बीच का फ़र्क़ मिट जाए। यह राजनैतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है जिसके अनुसार यह ज़रूरी है कि समाज में सभी तरह की आवाज़ें समान तौर पर सुनी जाएँ। इसकी अहम संस्था विचार-विमर्श के लिए जन विधानसभा है।

इन विधानसभाओं में गोष्ठियाँ होती हैं जहाँ नागरिक किसी विषय पर विभिन्न मतों को सुनकर, उन पर विचार-विमर्श कर बिना किसी दबाव के एक सामूहिक निर्णय पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र से अलग है जिसमें सरकारी नीतियों पर निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ तत्व जैसे जनमत संग्रह (referendum) आदि मौजूदा प्रतिनिधि लोकतंत्रों में भी पाए जाते हैं।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रथा बहुत पुरानी और प्राचीन है। पाँचवीं शताब्दी (ईसा पूर्व) के ऐथेंज़ को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण के तौर पर अक़्सर उद्धृत किया जाता है जहाँ वयस्क पुरुष नागरिक सार्वजनिक निर्णय-प्रक्रिया में सीधे हिस्सा लेते थे। ऐथेंज़ के लोकतंत्र का यह चरित्र जहाँ गुलामों, महिलाओं और विदेशियों को निर्णय-प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता था बताता है कि यह बहुत ही सीमित लोकतंत्र था हालाँकि इसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाओं और हिस्सेदारी के तरीक़ों के लिए यह प्रासंगिक है।

अग़र हम लोकतंत्र को 'चर्चा द्वारा शासन' के तौर पर सोचें तो इसकी जड़ें ऐथेंज़ के लगभग समकालीन एक लम्बी, ग़ैर-पश्चिमी प्रथा में भी हैं जैसे उत्तर भारत का नगर वैशाली और Sabarcae-Sambastai (जो अब पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में हैं) के लोग जिनके अनुभव प्राचीन भारतीय और यूनानी स्त्रोतों में भी दर्ज हैं। बौद्धिक स्त्रोतों के तौर पर एक अहम प्रभाव जीन जेकस रूसो और उनके प्रतिनिधित्व और सरकार पर विचार हैं।

रूसो के लिए अपने स्व-शासन का हक़ किसी और को सौंपना गुलामी का एक प्रकार था, और इसीलिए उन्होंने उन सभी क़ानूनों को अस्वीकृत कर दिया जिन पर नागरिकों ने पहले ही विचार-विमर्श कर सहमति ना बनाई हो। इससे जुड़ा एक अहम सिद्धांत 'स्वशासन' (या स्वायत्तता) का है। कस्टोरिदीयस (एक दार्शनिक) के अनुसार, स्वशासन का अर्थ है समाज की वह सामूहिक क्षमता जिससे वो लगातार समाज के नियमों/मानकों और संस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर सके और उन्हें बदल भी सकें। और इसका आधार यह विश्वास है कि स्वयं समाज ही ऐसा करने का एकमात्र वैध ज़रिया है।

कस्टोरिदीयस ने उन dogmas (ऐसे सिद्धांत जिन पर सवाल ना उठाए जा सकें) की आलोचना की जो बाहरी नियम थोपकर स्वायत्तता को कम करते हैं या जो समाज के बाहर की किसी शक्ति (जैसे ईश्वर, ऐतिहासिक ज़रूरत, आदि) का नाम लेकर सामूहिक निर्णयों को उचित ठहराते हैं, उन्होंने इस स्थिति को 'heteronomy' कहा। संक्षेप में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों को अपनी क़िस्मत सम्बंधी निर्णयों पर नियंत्रण रखने और भागीदारी वाली निर्णय-प्रक्रिया में उन्हें हिस्सा लेने लायक बनाता है बजाय इसके कि वे स्वार्थी राजनीतिज्ञों पर निर्भर रहें और इस तरह किए निर्णयों की वैधता भी उच्च कोटि की होती है (हेवुड, २००२)।

जहाँ तक उत्तर-विकास (post-development) की बात है (रहनेमा और बट्री १९९७), प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बदलाव/रूपांतरण की क्षमता को दो तरह से देखा जा सकता है: एक ओर, यह सोचने के एक-मात्र तरीक़ों और heteronomous कल्पनाओं के द्वारा दिमाग़ों पर क़ब्ज़ा जमाने को चुनौती देने में मदद करता है। दूसरी ओर, व्यावहारिक तौर पर, यह विकास के विकल्प तैयार करने में

मदद करता है। जिस तरह आधुनिक सामाजिक आंदोलन ही नहीं बल्कि ग़ैर-राज्य राजनैतिक व्यवस्थाएँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को काम में लेती हैं उससे इसकी क्षमता का सहज ही प्रमाण मिल जाता है।

स्पेन में, जन-विधानसभा-आधारित निर्णय-प्रक्रिया जो इनडिगनादोस् (Indignados) आंदोलन से लोकप्रिय हुई उसने 'आवास के अधिकार' सामाजिक आंदोलनों को मज़बूती देकर स्पैनिश पूँजीवाद के शहरी पूँजी संग्रह को विघटित कर दिया है (गारसिया, २०१७), और साथ ही बाध्यकारी नागरिक विचार-विमर्श के प्रावधानों द्वारा नगरपालिकाओं को न्यायपूर्ण और पर्यावरणीय तौर पर सतत मॉडल्ज़ को अपनाने के लिए बाध्य किया है।

भारत में, रैडिकल पारिस्थितिकीय लोकतंत्र की पहलें जैसे राजस्थान के ७२ नदी-तट के गाँवो की अरवरी नदी संसद उन प्रयासों की ओर इशारा करती है जो ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं जिसमें पारिस्थितिकीय इकाइयों की एक जैव-क्षेत्रीय (bio-regional) सोच हो और यह इकाइयाँ स्थानीय समुदायों द्वारा शासित हों और इनके मूल में सांस्कृतिक विविधता, मानव की बेहतरी और पारिस्थितिकीय लचीलापन हो।

कुर्दिश स्वायत्त कैंटॉन (प्रांत) रोजावा का प्रशासनिक ढाँचा जो राजनैतिक पदों और भागीदारी में लैंगिक समानता पर ज़ोर देता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनी निर्णय-प्रक्रिया में शामिल करता है। इसका उद्देश्य मरी बूकचिन के सामाजिक पारिस्थितिकी (social ecology) के मूल्यों के आधार पर समाज को बदलना है और इस तरह भविष्य के क्षेत्रीय शासन की परिसंघीय व्यवस्थाओं के लिए एक बेहतरीन संगठन बनना है।

और पूरे अमेरिकी महाद्वीप में कई मूलवासी, कैम्पेसीनो (किसान) और अफ़्रीकी वंशज समुदाय स्व-शासन के लिए जन-विधानसभा-आधारित निर्णय-प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जो उनके स्वशासन के मूल्यों, सामुदायिकता और उनकी वृहद ब्रह्मांडीय सोच (cosmovision) जो जीवन के विभिन्न रूपों के लिए इज़्ज़त रखने के मूल्यों से उपजी है उसे जीवंत करने का प्रयास करते हैं।

इसके विपरीत, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक 'कृष्ण' पक्ष भी है जो इसकी बदलाव रोकने की क्षमता में है। जैसे स्विटज़रलैंड का Appenzell-Innerrhoden प्रांत जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मिसाल के तौर पर मशहूर है वहाँ १९९१ में जाकर महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल पाया था और वह भी तब जब वहाँ के उच्चतम न्यायालय ने उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया। साथ ही, इस प्रांत में मीनारों का निर्माण करने पर रोक लगाने के पक्ष में भी सभी प्रांतों में से सर्वाधिक मतदान हुआ था।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसके समर्थक इसे बहुत रूमानी तौर पर देखते हैं और यह भूल जाते हैं कि आज के वैश्वीकृत विश्व में शायद राज्य-सत्ता बड़े क्षेत्रों में संसाधनों को लामबंद कर और समन्वय कर आमूल-चूल परिवर्तन लाने की बेहतर क्षमता रखती है।

आलोचक नागरिकों की हर समय दैनिक जीवन में शासन के विषयों में उलझे रहने की इच्छा पर भी सवाल उठाते हैं और इसे 'उदार वामपंथियों' का मात्र एक रूमानी सपना क़रार देते हैं और इसके लिए वे १८७१ के पेरिस कॉम्यून का उदाहरण देते हैं जो ज़्यादा टिक नहीं पाया और उनके अनुसार इसकी (प्रत्यक्ष लोकतंत्र की) सीमाओं का भी प्रमाण है।

अन्य आलोचक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के केंद्रीय तत्व यानी विचार-विमर्श की प्रक्रिया की सीमाओं की ओर ध्यान दिलाते हैं यह कहते हुए कि इन प्रक्रियाओं की वजह से कोई क्रांतिकारी सामाजिक-पारिस्थितिकीय बदलाव लाने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। मसलन, आलोचक कहते हैं कि सहमति के आधार पर निर्णय लेने पर ज़ोर देने से इन बदलावों को लाने में अपनी भूमिका निभाने वाले मतभेद, असहमति और अलगाव की महत्ता कम हो जाती है। वे यह भी कहते हैं कि आम-सहमति वाले निर्णयों पर पहुँचने के लिए दिए गए तार्किक वाद-विवाद पर ज़ोर देने से भावनाओं, कल्पना, कहानियाँ, समाजीकरण (socialisation) और शारीरिक गतिविधि आदि की बदलाव में भूमिका को कमतर आँका जाता है। और यह भी कि पुराने प्रमाण इस ओर इशारा करते हैं कि बदलाव लाने के लिए 'सशक्त नेतृत्व' 'समतलता' (यानी सभी के बराबर होने) से ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है।

इन सभी आलोचनाओं के बावजूद यह तय लगता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आदर्श और व्यवहार ने इतिहास में भी व्यक्तियों और समुदायों को अपनी दुनिया को अलग और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है और आज भी कर रहा है। इस स्वरूप में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दिमाग़ों को पराधीन होने से बचाने और सोचने, जीने और काम करने

के आधिपत्य-वादी (hegemonic) तरीक़ों को चुनौती देने की संभावनाएँ नज़र आती हैं। अपने बेहतरीन रूप में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अलग ही जीने का तरीक़ा बन जाता है।

अन्य संसाधन:

जलवायु परिवर्तन पर एक कुर्दिश प्रतिक्रिया

https://www.opendemocracy.net/uk/anna-lau-erdelan-baran-melanie-sirinathsingh/kurdish-response-to-climate-change.

Centre for Indigenous Conservation and Development Alternatives (CICADA), http://cicada.world.

García, Lamarca M. (2017), 'From Occupying Plazas to Recuperating Housing: Insurgent Practices in Spain', International Journal of Urban and Regional Research. Doi:10.1111/1468-2427.12386.

Heywood, Andrew (2002), Politics. New York: Palgrave Macmillan.

O'Connor, Kieran (2015), 'They Don't Represent Us', Summary of a discussion about democracy and representation between Jacques Rancière and Ernesto Laclau, http://www.versobooks.com/blogs/2008-don-t-they-represent-us-a-discussion-between-jacques-ranciere-and-ernesto-laclau.

Rahnema, Majid and Victoria Bawtree (eds) (1997), The Post-development Reader. London: Zed Books.

लेखक परिचय:

क्रिस्टस ज़ग्राफ़ोस Pompeu Fabra विश्वविद्यालय में Ramóny Cajal वरिष्ठ शोध फ़ेलो हैं. राजनीतिक पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्र में उनका शोध राजनैतिक द्वंद्व और पर्यावरणीय रूपांतरण पर केंद्रित है। वे बार्सीलोना के त्मेमंतबी - Research & Degrowth Collective के सदस्य हैं और चेक रिपब्लिक के Masaryk विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफ़ेसर हैं।

प्राकृतिक स्वराज

असीम श्रीवास्तव Aseem Shrivastava

प्रमुख शब्द: स्वराज, स्वदेशी, लोकतंत्र, आज़ादी

इस स्वराज को किसी सपने की तरह मत मानो - मोहनदास गांधी

२१वीं शताब्दी में स्वराज के बारे में बात करते हुए यह भरोसा होता है कि हम एक ऐसी सोच को खोजने और ताक़त देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका रिश्ता भारतीय दार्शनिक चिंतन, संस्कृति और राजनैतिक प्रथाओं की एक सशक्त घरेलू/स्वदेशी धारा से रहा है।

आइए 'स्वराज' शब्द पर मनन करते हैं। इसकी शाब्दिक उत्पत्ति संस्कृत के दो सरल शब्दों से हुई है - स्व (अपना) और राज्य (शासन) तो स्वराज का सीधा मतलब स्व-शासन से है। इसके साथ यहाँ जोड़ा गया शब्द 'प्राकृतिक' अपने इर्द-गिर्द के प्राकृतिक संसार के साथ ताल मिलाकर चलने की मानवीय प्रकृति का इज़हार करता है।

स्वराज का यह विचार किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक निर्वात में पैदा नहीं हुआ। प्राचीन भारत में- गावों के स्तर पर भी - रू-ब-रू राजनीतिक जनसभाएँ होने का प्रमाण मिलता है। मौखिक और लिखित दोनों ही तरह के स्त्रोत शासन की ऐसी परम्पराओं को उजागर करते हैं जहाँ चर्चा और सलाह-मशविरा कर शासन किया जाता था और कभी-कभी संवाद और आम-सहमति से निर्णय लिए जाते थे।

याद रखने लायक अहम बात यह है कि स्वराज जैसी संकल्पनाएँ-संस्कृत या पालि में, जिनसे आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की कुछ शब्दावली को लिया गया है ये शब्द औपनिवेशिक दौर से शताब्दियों और अक़्सर सहस्त्राब्दियों पुराने हैं और ये पश्चिमी दुनिया से भारत में आयातित संकल्पनाओं के अनुवाद मात्र नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संकल्पनाएँ भारतीय इतिहास के किसी ना किसी काल में प्रचलित थीं और फिर यह कहीं ग़ायब-सी हो गयीं विशेषत: आधुनिक काल में औपनिवेशिक शासन के आने के बाद।

तो गांधी जी ने 'ग्राम स्वराज' के विचार का सपना कहीं हवा से नहीं उठाया। १९०९ में उन्होंने अपनी सबसे अहम कृति 'हिंद स्वराज' लिखी। और गांधी जी ने आज़ादी के संघर्ष में पहले से इस्तेमाल हो रहे इस विचार को आगे बढ़ाया। बाल गंगाधर तिलक[१] ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दिनों में १८९० के दशक में इसे इस्तेमाल किया था।

स्वराज इस तरह 'लिबर्टी और इंडिपेंडेन्स' जैसी आधुनिक पश्चिमी धारणाओं के लगभग समकक्ष बन गया। १९०६ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर जब दादा भाई नौरोजी ने 'स्वराज' को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया तब उनके मन में इसका यही सीमित अर्थ था।

गांधी जी की सोच इससे कहीं आगे गयी। इसकी प्राचीन विरासत से वाक़िफ़ गांधी ने १९३१ में 'यंग इंडिया' में स्वराज को 'एक पवित्र शब्द, एक वैदिक शब्द' लिखा (गांधी, १९३१)। उनकी उम्मीद थी कि भारत और पूरी दुनिया एक दिन स्वराज के इस पुराने विचार को पाएगी और इसे हक़ीक़त बनाएगी।

गांधी के लिए असली स्वशासन सिर्फ़ तभी मुमक़िन हो सकता है जब व्यक्ति स्वयं अपना संप्रभु होने की क्षमता रखता हो। गांधी धार्मिक थे। उनका मानना था कि बिना आध्यात्मिक/नैतिक श्रेष्ठता (transcendence) के व्यक्ति के लिए अपने जीवन पर प्रभुता हासिल करना सम्भव नहीं है। उनके लिए यह धारणा उतनी ही आध्यात्मिक थी जितनी कि राजनीतिक। लेक़िन, अहम बात यह भी है कि कार्य-कारण सिद्धांत (causation) का प्रवाह इकतरफ़ा होता है।

अंतत:, गांधी के लिए स्वराज एक दैवीय आवश्यकता थी जो मानव के लिए अच्छे परिणाम वाली थी। आध्यात्मिक महारत और अपने पर प्रभुत्व करना भी राजनैतिक संप्रभुता के सुपरिणाम एक सह-उत्पाद के तौर पर दे सकता है लेक़िन इसका उलटा नहीं हो सकता।

राजनीतिक तौर पर, स्वशासन, जैसा कि गांधी जी ने इसे समझा, वह आधुनिक संसदीय या प्रतिनिधि लोकतंत्र जैसा क़तई था। 'हिंद स्वराज' में उन्होंने आधुनिक संसदों को 'गुलामी के प्रतीक' बताया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वराज को अक़्सर 'लोकतंत्र' के तौर पर परिभाषित/अनूदित किया जाता है। सच तो यह है कि अपने प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप में लोकतंत्र को बहुत से देशों में अपनाया तो गया है लेकिन इनके संज्ञानात्मक (cognitive) आधार बहुत अलग हैं।

प्रथम तो स्वराज आज के लोकतंत्र के रोज़मर्रा के तथ्य 'सामूहिक राजनीति' (mass politics) से मेल नहीं खाता। जहाँ सीमित, रु-ब-रु मोहल्ला/बस्ती सभाएँ नहीं हो सकती वहाँ स्वराज काम नहीं कर सकता। भीड़ किसी लोकतंत्र की सियासी पार्टियों की मशीन को तेल दे सकती है, स्वराज को नहीं। संख्या और उनकी आपस में तुलना आधुनिक प्रजातंत्र के लिए जितनी अहम है स्वराज के लिए वे उतनी ही अप्रासंगिक हैं।

दूसरा, आधुनिक लोकतंत्र एक व्यक्ति के सीधे, बिना किसी मध्यस्थता के उस राज्य से रिश्ते पर केंद्रित होता है जिससे उसे क़ानून के तहत नागरिकता का अधिकार मिलता है। इस सम्बंध के लिए जो परिदृश्य सोचा गया है वह एक ऐसे समाज का है जहाँ व्यक्ति 'विखंडित' (atomised) है और मानवीय विलगाव (alienation) सामान्य हो चुका है। इसके विपरीत, अपने पोषण के लिए स्वराज को जो चाहिए वह है एक ऐसा समुदाय जहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व को अपने पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय सम्बन्धों (ना सिर्फ़ मानव बल्कि अन्य सभी सजीव जीवों के साथ) के ज़रिए मुक़म्मल बना पाए।

तीसरा, एक आधुनिक लोकतंत्र में, एक व्यक्ति को, लगभग उदासीन तरीक़े से, और 'आज़ादी' के नाम पर, अपनी पसंद और अभिलाषाओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है - देखा जाए तो पूरा आधुनिक अर्थशास्त्र इसी धारणा पर आधारित है, समुदाय का इन चीज़ों को परखने में व्यक्ति की मदद करने का कोई सवाल ही नहीं है। और व्यक्ति पर यह दारोमदार बिल्कुल भी नहीं है कि वह अपनी अभिलाषाओं की समीक्षा करे तब तक जब तक कि उन इच्छाओं को पूरा करने में किसी और की इच्छा-पूर्ति में बाधा ना आती हो।

वस्तुत:, आधुनिक उदार लोकतंत्र में 'आज़ादी' की परिभाषा ही यही है जिसे अक़्सर 'नकारात्मक स्वतंत्रता' के रूप में समझा जाता है। गांधी के स्वराज के विचार में एक व्यक्ति या समुदाय को यह स्वायत्तता हासिल होती है जिससे कि वे अपनी पसंद 'बना' सकें बशर्ते कि सिर्फ़ पहले से उन्हें दी गयी सूची में से 'चुन' लें।

इस सोच को अग़र हम अपनी बाज़ार-आधारित, मीडिया-संचालित दुनिया में देखें तो पहले तो हमें अपनी इच्छाओं की पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक जिम्मेदारी लेते हुए देखना होगा कि कहाँ तक हमारी इच्छाएँ विज्ञापनों से प्रभावित उन्माद में पैदा होती हैं। इच्छाओं का इस तरीक़े का कार्य-साधन के लिए इस्तेमाल जिसमें एक तरह से हर एक चीज़ दाँव पर लगी हो यह स्वराज के किसी भी समर्थक के लिए विरोधात्मक है।

इच्छा, जो आज के उपभोक्ता लोकतंत्र में आज़ादी के सिद्धांत के दार्शनिक हृदय में है उस की स्वराज के तहत सूक्ष्म रूप से समीक्षा करनी होगी विशेषत: तब जब दुनिया एक पारिस्थितिकीय संकट से गुज़र रही है। इसका एक अर्थ यह है कि गांधी का स्वराज का विचार 'स्वदेशी' के विचार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है और यह आर्थिक स्थानीयकरण (localisation) की दरकार भी करता है।

अंतत:, यह बताना ज़रूरी है कि स्वराज का विचार भारत में सामाजिक, राजनैतिक और पारिस्थितिकीय आंदोलनों को आज भी प्रेरित कर रहा है। विकास के नाम पर हो रहे विस्थापन का विरोध करने वाले कई आंदोलन जो जन-आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) के तहत काम करते हैं, हाल ही में बनाई गयी 'स्वराज इंडिया' पार्टि जो ज़मीन पर लोगों को सशक्त करने के उद्देश्य से बनाई गयी है, खाद्य संप्रभुता के आंदोलन हों या आदिवासी और मूलवासियों के स्व-शासन के आंदोलन ये सभी स्वराज के विचार को आज के संदर्भ में रचनात्मक तौर पर ढालने की कोशिशें हैं।[२]

नोट:

१. बाल गंगाधर तिलक, १९वीं सदी के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक।

२. स्वराज इंडिया के लिए देखें- https://www.swarajabhiyan.org/; जन-अभियानों के राष्ट्रिय समन्वय (NAPM) के लिए देखें https://napmindia.wordpress.com/; यह भी देखें

Food Sovereignty Alliance https://foodsovereigntyalliance.wordpress.com/

अन्य संसाधन :

Gandhi, Mohandas Karamchand (1931), Young India, March 19, Ahmedabad.

——— (2010), Hind Swaraj: A Critical Edition. Annotated, edited and translated by Suresh Sharma and Tridip Suhrud. Delhi: Orient Blackswan.

Muhlberger, Steven (2011), 'Republics and Quasi-Democratic Institutions in Ancient India', in Benjamin Isakhan and Stephen Stockwell, The Secret History of Democracy. London: Palgrave Macmillan.

लेखक परिचयः

असीम श्रीवास्तव एक दिल्लीवासी लेखक एवं पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्री हैं। वे University of Massachusetts, Amherst से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर चुके हैं। उन्होंने आशीष कोठारी के साथ मिलकर Churning the Earth: The Making of Global India (Penguin Viking, 2012) नामक पुस्तक का लेखन किया। वे वर्तमान में रबिन्द्र नाथ टैगोर के पारिस्थितिकीय चिंतन का अध्ययन करने की एक परियोजना में संलग्न हैं।

क्रांति (Revolution)

एदुआर्दो गुडिनास Eduardo Gudynas

प्रमुख शब्द: क्रांति, विकास, ओंटोलोजी (ontology), पूँजीवाद, समाजवाद

वक़्त आ गया है कि जब हम 'विकास' के विचार के पीछे भागने की बजाय अपना रास्ता बदलें। आज हम जिस सामाजिक और पर्यावरणीय संकट की स्थिति में हैं ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है; जिस तरह तेज़ गति से पर्यावरण का विनाश हो रहा है और लोगों की आजीविका छिन रही है ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है, और यह तात्कालिक है क्यूँकि इसे अपनाना आज और अभी सम्भव है।

यह ज़रूरी है कि क्रांति का एक नया अर्थ विकास के वैचारिक आधार पर सवाल उठा सके और आधुनिकता (modernity) के परे जा सके। क्रांति का विचार कई अहम राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का उल्लेख करता है।

फ़्रांसीसी क्रांति को जाने-माने उदाहरण के तौर पर लें तो एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था से छुटकारा पाने और राजनैतिक प्रतिनिधित्व के तरीक़ों और संस्थाओं को बदलने और समाज के आर्थिक और सामाजिक ढाँचों को बदलने के लिए क्रांति अपरिहार्य है। हालाँकि अलग-अलग मात्रा और ज़ोर के साथ लेकिन यह विचार मेक्सिको, रूस, चीन, क्यूबा और अन्य देशों में हुए आमूलचूल बदलावों के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्रांति के विचार ने पारम्परिक विकास की प्रथाओं को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई है, जैसे औद्योगिक, प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और उपभोक्ता क्रांति। इन क्रांतियों ने समाज के ढाँचे में अहम बदलाव लाते हुए विकास के मूल विचारों को ही बल दिया।

इनसे ताज़ा घटनाओं ने इस विचार को कुछ उलझा दिया है। कुछ इलाक़ों में आज भी महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन क्रांति की पारम्परिक धारणाओं को बचाने में लगे हुए हैं मसलन पूँजीवाद को छोड़कर समाजवाद की ओर जाने के लिए। केंद्रीय और पूर्वी यूरोप में, 'असली समाजवाद' (Real Socialism) को छोड़ना एक क्रांति की तरह पेश किया गया, हालाँकि विपरीत दिशा में यानी बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर। इसके विपरीत, समाजवादी क्रांति के प्रयासों, जैसे चीन और वियतनाम में ऐसा विमर्श (discourse) चलाया गया लेक़िन असल में उनकी विकास की रणनीतियाँ पूँजीवाद के पक्ष में हैं। और जहाँ विकास के यूरो-केंद्रित होने पर हमला करते हुए इस्लामिक क्रांतियाँ हुईं वे आर्थिक वृद्धि का समर्थन करती हैं।

२१वीं सदी की शुरुआत से, लैटिन अमेरिका ने एक 'लेफ़्ट टर्न' लिया है और यहाँ कई सरकारों ने अपने-आप को क्रांतिकारी क़रार दिया है जैसे- वेनेज़ुएला, बोलिविया, इक्वाडोर और निकारागुआ। लेकिन इन देशों ने नव-विकासवादी व्यवस्थाओं को अपनाया है जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुँध दोहन से आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने की ओर क़दम बढ़ाए हैं।

इस तरह, हम ऐसी कई घटनाओं से घिरे हुए हैं जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया (विशेषत: राजनीतिक मायनों में) लेक़िन जिनका समाज के सांस्कृतिक आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ा। हालाँकि इन सभी मामलों में 'विकास' के बुनियादी हिस्से बचे रहे जैसे आर्थिक वृद्धि, उपभोक्तावाद, प्रकृति का दोहन, प्रौद्योगिकी में आधुनिकता और कमज़ोर लोकतंत्र। यह काफ़ी विरोधाभासी स्थिति है जहाँ रूस और चीन की क्लासिक क्रांतियाँ हों या हालिया क्रांतियाँ जैसे दक्षिणी अमेरिका में २१वीं सदी के समाजवाद वाली क्रांतियाँ, चाहे धार्मिक हों या पंथ-निरपेक्ष, सभी अंतत: 'विकास' के विचार की तरफ़ मुड़ी हैं।

इनमें से कुछ क्रांतियों ने राजनैतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता के सम्बंध में सकारात्मक परिणाम दिखाए लेक़िन वे राज्य-सत्ता हासिल करने के लिए ज़रूरी सहायक लक्ष्यों में ही उलझ कर रह गए (विशेषत: लेनिन-वादी, ट्रोत्सकी-वादी और माओ-वादी)। वे सभी विकास के विकल्पों को बढ़ावा देने में विफल रहे।

इसे इस बात से समझाया जा सकता है कि सभी आधुनिक राजनैतिक परम्पराओं की पृष्ठ-भूमि एक ही रही है। वस्तुत: क्रांति का विचार आधुनिकता की अन्य श्रेणियों के साथ ही परिपक्व हुआ जैसे राज्य, अधिकार, लोकतंत्र, प्रगति और विकास।

विकासवाद के जारी रहने ने कई ऐक्टिविस्ट और अकादमिक लोगों का क्रांतिकारी प्रयासों से विश्वास उठा दिया है, और वे यह तर्क देने लगे हैं कि क्रांति का यह विचार वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता और इसके बजाय स्थानीय प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए।

लेक़िन यह स्थिति एक अहम बाधा पैदा करती है, विकास के किसी रैडिकल विकल्प का मतलब है कुछ क्रांतिकारी बदलाव। जब विकास के सभी वर्तमान प्रकार टिकाऊ नहीं हैं तो ऐसे में किसी रैडिकल विकल्प को आधुनिकता के अपने साझा आधारों पर सवाल उठाने ही होंगे। ऐसे किसी रैडिकल प्रयास के लिए क्रांतिकारी भावना और काम की ज़रूरत है।

मसलन आधुनिक अर्थ में क्रांति का मतलब किसी राज्य की सरकार बदलना या एक प्रकार के विकास की बजाय दूसरे प्रकार का विकास लाना हो सकता है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि क्रांति के विचार का एक नया अर्थ बनाया जाए जो आधुनिकता से परे जाने और इसकी ओंटोलोजी के एक विकल्प की कल्पना कर सके।

क्रांति के इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिकता के बनिस्बत एक विद्रोह करना होगा जो इसकी सीमाओं पर प्रकाश भी डाले और इसके विकल्प भी खोजे। इसके लिए ज़रूरत है एक नवप्रवर्तन की कल्पना की जिससे इसकी तार्किकता और संवेदनाओं को उकेरा जा सके और इसकी तैयारी की जा सके। साथ ही एक विस्तारित राजनीति की भी जिसमें कई सामाजिक क्षेत्र, प्रथाएँ और तजुर्बे शामिल हों।

क्रांति की यह समझ 'Pachacuti' के ऐंडीयन विचार से काफ़ी समानता रखती है। 'Pachacuti' से तात्पर्य मौजूदा ब्रह्मांडीय व्यवस्था को भंग कर अव्यवस्था की स्थिति क़ायम करना है जिससे एक नई ब्रह्मांडीय दृष्टि उभर सके। इस तरह, Pachacuti के अनुसार एक क्रांति आधुनिकता को तबाह करने की कोशिश नहीं करती बल्कि इसके ढाँचों के विघटन और अव्यवस्था को जगह देने की कोशिश करती है और साथ ही वैकल्पिक समझ और परिणाम भी पैदा करती है। इसमें एक महत्वपूर्ण नव-निर्माण भी शामिल है।

इस प्रकार की क्रांति के कई पद-चिन्ह हमें इतिहास में मिलते हैं। अव्यवस्था और नव-निर्माण का यह अनुभव तार्किक विचारों जैसे सामाजिक और पर्यावरणीय संकट के प्रमाणों और साथ ही उत्तेजक, कलात्मक, आध्यात्मिक और जादुई अनुभवों से भी पोषित होता है। ऐसी क्रांति एकल-संस्कृति को नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की विविधता को बढ़ावा देती है, यह सामूहिक होती है और इसके लिए व्यक्तिगत बदलाव भी ज़रूरी होता है। विशेषत: जीवन के मोल को वापस लाने के लिए --- महात्मा गांधी, इवान इलिच, zapatismo, buen vivir इत्यादि इसके कुछ मॉडल प्रदान करते हैं।

क्रांति इस अर्थ में उपयोगिता-वादी मूल्यों से अलग हटकर किसी को तोलने के कई पैमाने वापस लाने की जगह बनाती है - जैसे सौंदर्यपरक, धार्मिक या पारिस्थितिकीय और साथ ही ग़ैर-मानव दुनिया के 'निहित मूल्य' को भी स्वीकारती है। चूँकि विकास एक प्रदर्शनात्मक रचना (performative construct) है जिसे हम सभी के द्वारा रोज़मर्रा की प्रथाओं से बनाया और फिर बनाया जाता है यह क्रांति उस प्रदर्शनात्मकता को रोकती है। जैसे यह समाज और प्रकृति के वस्तु-करण (commodification)को रोकती है। इस तरह आधुनिकता की यह विशेषतायें अव्यवस्थित हो जाती हैं और एक अपरिहार्य और कभी-कभी असहज परिणाम की ओर ले जाती हैं यानी: एक ऐसी क्रांति जो पूँजीवाद और समाजवाद दोनों से ही भिन्न होती है।

इस क्रांति की झलक दिखाती प्रथाएँ संयुक्त-क्रियाओं (synergy) के साथ आपस में जुड़ी होती हैं, और पूरे समाज में फैलते हुए, अपने कामों, प्रभावों और राजनीति की अन्य शैलियों में ठोस होती रहती हैं, विशेषत: गरिमा और स्वायत्तता से उपजे विद्रोह से। यह एक ऐसी क्रांति होती है जो ग़ैर-मानवीय यानी पशु और अन्य सजीव प्राणियों के सहयोग से बनती है। यह समाज के अर्थ को पुनर्परिभाषित करती है। एक 'पशु सर्वहारा' (animal proletariat) की सम्भावना को ही लें।

इस प्रकार की क्रांति समाज और क़ुदरत के बीच के द्वंद्व को अव्यवस्थित कर देती है और ऐसी संबंधात्मक जीवन-दृष्टियों का निर्माण होने देती है जो समाज को क़ुदरत और क़ुदरत में समाज को पुनर्स्थापित (re-embed) करती हैं। यह ग़ैर-मानव जगत को भी 'subject' यानी चेतना-युक्त प्राणी का दर्जा देती है। संक्षेप में, एक ओर जहाँ आधुनिकता अपने-आप को एक

सार्वभौमिक और आत्म-सम्पूर्ण क्षेत्र की तरह दिखाती है वहीं यह अपनी सीमाओं को छुपा लेती है और इसके विकल्पों को खोजने के प्रयासों को ख़त्म कर देती है। यह क्रांति आधुनिकता की सीमाओं को अव्यवस्थित कर उसका पर्दाफ़ाश करते हुए इसे दूसरी ontologies के लिए खोलती है। इस तरह क्रांतिकारी काम का मतलब नई ontological openings की सम्भावनाओं के लिए ज़मीन तैयार करना है।

अन्य संसाधन :

Holloway, John (2003), Change the World without Taking Power: The Meaning of Revolution Today. London: Pluto Press.

Williams, Raymond (1983), 'Revolution', in Raymond Williams (ed.), Keywords. New York: Oxford University Press.

लेखक परिचय:

एदुआर्दो गुडनयस उरग्वे के Latin American Center for Social Ecology (CLAES), Montevideo में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। कैलिफ़र्न्या विश्वविद्यालय (Davis) के मानवशास्त्र विभाग में एसोसिएट शोधार्थी हैं और दक्षिणी अमेरिका के कई ज़मीनी जन-संगठनों के सलाहकार भी हैं।

ईको–समाजवाद (Eco-Socialism)

माइकल लोवी Michael Löwy

प्रमुख शब्दः पूँजीवाद, ईको-समाजवाद, मार्क्सवाद, उपभोग, असल ज़रूरतें, गुणात्मक रूपांतरण

पूँजीवादी व्यवस्था असीमित 'विकास', 'वृद्धि' और 'फैलाव' के बिना नहीं चल सकती। और इसीलिए एक रैडिकल उत्तर-विकासवादी विकल्प का उत्तर-पूँजीवादी (post-capitalist) भी होना ज़रूरी है। ईको-समाजवाद ऐसी ही एक वैकल्पिक व्यवस्था है।

यह पारिस्थितिकीय चिंतन और व्यवहार की एक धारा है जो मार्क्सवाद के आधारों पर टिकी है हालाँकि इस के 'उत्पादकता-वादी' (productivist) कचरे से अपने को दूर करते हुए। ईको-समाजवादी बाज़ार के तर्क और नौकरशाही की तानाशाही के तर्क दोनों को ही पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत के साथ बेमेल मानते हैं।

रेचल कार्सन, जेम्ज़ ओ'कॉनर (USA), आन्दरे गोर्ज़ (फ्रांस), फ़्रीडर-अटो वोल्फ़्फ (जर्मनी) और स्पेन के मैन्वेल सैक्रिस्टन आदि ईको-समाजवाद के प्रणेता हैं। और इनके बाद जोल कोविल, जॉन बेलमी फ़स्टर और ईयन ऐंगस आदि ने ईको-समाजवादी तर्कों की धार तेज़ की है।

पूँजीवादी संग्रह, विस्तार और विकास की तार्किकता-विशेषतः इसके समसामयिक नव-उदारवादी स्वरूप में-लघु-कालीन गणनाओं पर आधारित है और पारिस्थितिकीय तार्किकता और प्राकृतिक चक्रों की दीर्घ-कालीन सुरक्षा के ख़िलाफ़ है। निर्मम प्रतियोगिता, मुनाफ़ाख़ोरी की माँगें, वस्तुओं के प्रति उन्माद की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का समाज या राजनैतिक शक्तियों के परे एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में बदलना यह सभी प्रकृति के संतुलन को बर्बाद करते हैं।

एक रैडिकल वैकल्पिक आर्थिक नीति सामाजिक ज़रूरतों और पारिस्थितिकीय संतुलन के ग़ैर-मौद्रिक आधारों पर टिकी होगी। अधिकाधिक मुनाफ़ा कमाने की छोटे (या व्यक्तिगत) स्तर की तार्किकता के बजाय सामाजिक और पारिस्थितिकीय व्यापक-स्तरीय तार्किकता को लाने के लिए सभ्यता-गत प्रतिमानों को ही बदलना होगा ना सिर्फ़ उत्पादन बल्कि उपभोग, संस्कृति, मूल्य और जीवन शैलियों के सम्बंध में।

एक ईको-समाजवादी समाज में उत्पादक प्रणाली के सभी क्षेत्रों का पुनर्गठन कर नए क्षेत्र तैयार करने होंगे ताकि पूर्ण रोज़गार दिया जा सके। लेक़िन यह उत्पादन के साधनों पर लोकतांत्रिक नियोजन से सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित किए बिना नहीं हो सकता। निवेश और प्रौद्योगिकी-गत परिवर्तनों से सम्बंधित निर्णय बैंकों और पूँजीवादी उद्यमों के बजाय सार्वजनिक भलाई के उद्देश्य से होने चाहिएँ।

जो अर्थव्यवस्था ईको-समाजवाद की ओर बढ़ रही हो, उसे, जैसा कि कार्ल पोलान्यी ने कहा, अपने सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण में पुनर्स्थापित होना चाहिए। लोकतांत्रिक नियोजन का मतलब है कि निवेश सम्बंधी निर्णय जनता द्वारा लिए जाएँ ना कि 'बाज़ार के नियमों द्वारा' और ना ही किसी सर्वज्ञ पोलित-ब्यूरो द्वारा। निरंकुश होने के बजाय ऐसा नियोजन एक समाज की आज़ादी का प्रयास है, विलगाव (alienation) से आज़ादी और 'वस्तु-वादी आर्थिक क़ानूनों' (reified economic laws) से भी।

नियोजन और मज़दूरी के समय में कमी लाना दो ऐसे निर्णायक क़दम हैं जिन्हें मार्क्स ने 'स्वतंत्रता का राज' कहा। ख़ाली समय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी वस्तुतः काम-काजी लोगों के लोकतांत्रिक चर्चाओं और समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के प्रबंधन के लिए ज़रूरी है।

पूँजीवाद की विनाशक प्रगति से समाजवाद की ओर बढ़ना एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, साथ ही समाज, संस्कृति और सापेक्षता का एक स्थायी और क्रांतिकारी बदलाव है। यह संक्रमण ना सिर्फ़ उत्पादन के नए तरीक़े और एक समानतावादी समाज लाएगा बल्कि एक वैकल्पिक 'जीवन का तरीक़ा' भी लाएगा - एक नयी ईको-समाजवादी सभ्यता जो पैसे के राज से परे होगी।

सामाजिक और राजनैतिक ढाँचों का ऐसा क्रांतिकारी बदलाव अधिकतम जनता के एक ईको-समाजवादी

कार्यक्रम के प्रति सक्रिय सहयोग के बिना नहीं शुरू हो सकता। समाजवादी चेतना और पारिस्थितिकीय जागरूकता का विकास एक प्रक्रिया है जहाँ लोगों के संघर्ष के अपने सामूहिक अनुभव और स्थानीय तथा आंशिक टकराव निर्णायक तत्व हैं।

कुछ पारिस्थितिकी-विदों का मानना है कि 'उत्पादकता-वाद' का एकमात्र विकल्प वृद्धि को पूरी तरह रोक देना है या इसे नकारात्मक वृद्धि से बदलना है जिसे फ्रांसीसी 'decroissance' कहते हैं। यह उपभोग में भारी कमी लाने पर निर्भर है जिसमें ऊर्जा-खपत पर ख़र्च को आधा कर दिया जाए और व्यक्तिगत स्तर पर लोग सेंट्रल हीटिंग, वॉशिंग मशीन आदि का इस्तेमाल करना छोड़ दें।

ईको-समाजवादी इसके बजाय उत्पादन और उपभोग के एक 'गुणात्मक बदलाव' पर ज़ोर देते हैं। इसका मतलब है कि पूँजीवाद द्वारा संसाधनों की भारी बर्बादी को रोका जाए जो बेकार के या हानिकारक उत्पादों (जैसे कि हथियार उद्योग) के बड़े स्तर पर उत्पादन से होता है।

पूँजीवाद द्वारा उत्पादित कई वस्तुएँ तो स्वत: ही बेकार होती हैं जिन्हें तुरंत बदलने के लिए बेकार ही बनाया जाता है ताकि मुनाफ़ा कमाया जा सके। एक ईको-समाजवादी दृष्टिकोण से मुद्दा 'अत्यधिक उपभोग' नहीं है बल्कि उपभोग का 'प्रकार' है। व्यापारिक विलगाव (**mercantile** alienation) पर आधारित अर्थव्यवस्था और 'फ़ैशन' के पीछे भागते हुए हर वक़्त नई-से-नई वस्तुएँ ख़रीदने की लत पारिस्थितिकीय तार्किकता से मेल नहीं खाती।

एक नए समाज में उत्पादन बुनियादी ज़रूरतों (जैसे पानी, खाना, कपड़े, आवास, आदि) को पूरा करने और मूलभूत सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात आदि उपलब्ध कराने की ओर प्रेरित होगा।

असल ज़रूरतों को उन कृत्रिम या काल्पनिक ज़रूरतों से बहुत आसानी से अलग किया जा सकता है जो छल-पूर्ण विज्ञापन जगत ने पैदा की हैं। 'विज्ञापन' पूँजीवादी बाज़ारू अर्थव्यवस्था का अपरिहार्य हिस्सा है लेकिन समाजवाद की ओर क़दम बढ़ाते समाज में इसकी कोई जग़ह नहीं है।

यहाँ वस्तुओं और सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी उपभोक्ता संगठनों से प्राप्त होगी। असल ज़रूरतों को बनावटी ज़रूरतों से अलग करने की सीधी सी परीक्षा यह है कि क्या वे विज्ञापनों के बंद होने के बाद भी बनी रहती हैं!

ईको-समाजवादी लोग एक व्यापक अंतराष्ट्रीय गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गठबंधन में मज़दूर आंदोलन, पारिस्थितिकीय, मूलवासी, किसान, नारीवादी और वैश्विक उत्तर और दक्षिण के कई मशहूर आंदोलन शामिल हैं। ये संघर्ष शायद एक समाजवादी और पारिस्थितिकीय विकल्प तैयार करने में सफल हों लेकिन पूँजीवाद के अवश्यंभावी अंतर्विरोधों की वजह से नहीं और ना ही 'इतिहास के अवश्यंभावी क़ानूनों' (iron laws of history) की वजह से।

भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता (सिर्फ़ सशर्त आधारों के अलावा)। लेकिन जो साफ़ है वह यह है कि ईको-समाजवादी रूपांतरण के बिना यानी सभ्यता के प्रतिमान में आमूल-चूल परिवर्तन के बिना पूँजीवाद का तर्क तो हमें सिर्फ़ नाटकीय पारिस्थितिकीय त्रासदियों की ओर ही ले जाएगा। अरबों लोगों के स्वास्थ्य और यहाँ तक कि जिंदगियाँ ख़तरे में डालेगा और यहाँ तक कि हमारी प्रजाति का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा।

अन्य संसाधन :

Angus, Ian (2016), Facing the Anthropocene. New York: Monthly Review Press.

Bellamy Foster, John (2009), The Ecological Revolution. New York: Monthly Review Press.

Capitalism Nature Socialism, http://www.tandfonline.com/loi/rcns20.

Climate and Capitalism, http://climateandcapitalism.com.

Kovel, Joel (2007), The Enemy of Nature. London: Zed Books.

Lowy, Michael (2015), Ecosocialism: A Radical Alternative to Capitalist Catastrophe. New York: Haymarket Books.

लेखक परिचय:

माइकल लोई एक दार्शनिक हैं। उनका जन्म १९३८ में ब्राज़ील में हुआ और वे १९६९ से पेरिस में रह रहे हैं। वे वर्तमान में वहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान के राष्ट्रीय सेंटर (CNRS) में एमेरिटस रीसर्च डायरेक्टर हैं; उनकी किताबें और आलेख २९ भाषाओं में अनूदित हो चुके हैं। उन्होंने २००१ में अमेरिका के जर्नल Capitalism Nature Socialism के सम्पादक दिवंगत जोल कोविल के साथ मिलकर 'दी इंटर्नैशनल ईको-सोशलिस्ट मैनिफ़ेस्टो' तैयार किया था।

सामाजिक पारिस्थितिकी (Social Ecology)

ब्रायन टोकर Brian Tokar

प्रमुख शब्द: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, पारिस्थितिकी, परिसंघ (confederation), अधिक्रम (hierarchy), समुदाय, विधानसभा, सामाजिक आंदोलन

सामाजिक पारिस्थितिकी एक क्रांतिकारी और पुननर्माण की राजनीतिक दृष्टि देता है। यह मानव समुदायों और प्रकृति जगत के बीच के रिश्ते पर पारम्परिक विचारों को चुनौती देते हुए एक स्वतंत्र, परिसंघित और प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले शहर, क़स्बों और बस्तियों की एक वैकल्पिक दृष्टि देता है जिसका उद्देश्य इन रिश्तों को पुनः सद्भावपूर्ण बनाना है।

सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा के जनक सामाजिक-सिद्धांत-वेत्ता मरी बूकचिन थे। १९६० के दशक से २००० के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करते हुए और उनके साथियों और दुनिया भर में कई दूसरे लोगों ने इसे आगे बढ़ाया है। सामाजिक पारिस्थितिकी का विचार कई सामाजिक आंदोलनों में प्रभावी रहा है। चाहे १९७० के दशक के नाभिकीय (nuclear) ऊर्जा के ख़िलाफ़ अभियान हों या वैकल्पिक-वैश्वीकरण या पर्यावरण न्याय सम्बंधी आंदोलन या फिर तुर्की और सीरिया में वर्तमान में चल रहे कुर्द समुदाय के लोकतांत्रिक स्वायत्तता के संघर्ष।

सामाजिक पारिस्थितिकी इस समझ के साथ आगे बढ़ता है कि पर्यावरण सम्बंधी समस्याएँ मूलतः सामाजिक और राजनैतिक समस्याएँ हैं और इनकी जड़ें प्रभुत्व और सामाजिक असमानता की हमारी ऐतिहासिक विरासत में हैं।

इसकी जड़ें अराजकतावादी और मुक्तिवादी (libertarian) समाजवाद की धारा में हैं, यह पूँजीवाद और राज्य-सत्ता पर भी सवाल खड़े करता है और स्थानीय लोकतंत्र के संस्थानों को केंद्रिकृत राज्य शक्ति का बेहतरीन उपाय मानता है। मरी बूकचिन पश्चिम के विचारकों में शायद पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने यह पहचाना कि पूँजीवाद तभी आगे बढ़ सकता है जब आर्थिक वृद्धि लगातार बढ़ती रहे और उन्होंने इसे जैविक पारिस्थितिकीय-तंत्रों के लिए बुनियादी ख़तरा मानते हुए कहा कि सामाजिक और पारिस्थितिकीय चिंताओं को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।

इतिहास और मानव-शास्त्र में अपनी विस्तृत खोज-बीन के द्वारा बूकचिन ने इस आम पश्चिमी धारणा को चुनौती दी कि मानव अपनी अंतर्निहित प्रवृत्ति के चलते प्राकृतिक जगत पर प्रभुत्व क़ायम करना चाहते हैं। इसके बजाय उनके अनुसार प्रकृति पर नियंत्रण एक मिथक है जिसकी जड़ें यूरोप और पश्चिमी एशिया में प्राचीन जनजाति समाजों के टूटने और लोगों के एक-दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की लालसा से उपजे रिश्तों में हैं।

सामाजिक पारिस्थितिकी-वादी उत्तरी अमेरिका के मूलवासियों और critical social theory के अनेक स्कूल्ज़ से भी प्रभावित हैं, साथ ही इतिहास पर आधारित दृष्टिकोण पारिस्थितिकीय नारीवाद से भी जिसे Ynestra King और Chaia Heller ने प्रतिपादित किया।

इन प्रभावों के चलते, सामाजिक पारिस्थितिकी का विचार कई समता-मूलक सामाजिक सिद्धांतों पर ज़ोर देता है जो कई वर्तमान और पुरानी मूलवासी संस्कृतियों के समान रूप से हिस्से रहे हैं और इन्हें एक नई सामाजिक व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक के तौर पर ऊँचा उठाता है।

इन सिद्धांतों को आलोचनात्मक मानव-शास्त्रियों ने भी और मूलवासी विचारकों ने भी ऊँचा उठाया है और इसमें अंतर-निर्भरता, प्रतिदान (reciprocity), विविधता में एकता और पूरकता (complimentarity) की नीति आदि शामिल हैं। इस तरह यह विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की भूमिका में एक संतुलन पैदा करने की बात करता है विशेषतः यह ध्यान रखते हुए कि व्यक्ति भी बहुत अलग-अलग प्रकार के होते हैं।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों और अधिकाधिक विषम और असमानता वाले समाजों में अंतर्निहित द्वंदों ने ही एक तरीक़े से आज़ादी और प्रभुत्व क़ायम करने की विरोधी विरासतों के ज़रिए अधिकतर मानव इतिहास रचा है।

सामाजिक पारिस्थितिकी की दार्शनिक तलाश प्राकृतिक उद्भव (natural evolution) की प्रक्रियाओं में

से मानव चेतना के उभरने की प्रक्रिया के परीक्षण की होती है। द्वंद्वात्मक प्रकृतिवाद (dialectical naturalism) का दृष्टिकोण उद्भव के इतिहास की गतिशील ताक़तों का परीक्षण करता है और सांस्कृतिक उद्भव को एक द्वंद्वात्मक विकास के तौर पर देखता है जो प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही कारकों से प्रभावित होता है।

सामाजिक पारिस्थितिकी के विचारक उन मौजूदा विचारों पर सवाल उठाते हैं जो प्रकृति को 'ज़रूरत के क्षेत्र' के तौर पर देखते हैं। जिस तरह प्राकृतिक उद्भव में विविधता और जटिलता के उन्नत गुण होते हैं और जिस तरह इसने मानवीय रचनात्मकता और स्वतंत्रता के बीज बोए हैं हमारे समाजों के लिए यह ज़रूरी है कि वे (उद्भव की) इन अंतर्निहित प्रवृत्तियों को पूरी तरह अभिव्यक्त कर सकें और उन्हें परिष्कृत कर सकें।

ये ऐतिहासिक और दार्शनिक खोजें सामाजिक पारिस्थितिकी की राजनैतिक रण-नीति की नींव है जो मुक्तिवादी (libertarian) या confederal municipalism या और भी सरल 'communalism' कही जा सकती है और जिसकी जड़ें १८७१ के पेरिस कॉम्यून के अहम विचारों की विरासत में हैं।

सामाजिक पारिस्थितिकी 'पॉलिटिक्स' शब्द की यूनानी जड़ों की ओर फिर ले जाती है जहाँ politics का अर्थ 'पोलिस' (polis) यानी नगरपालिका के लोकतांत्रिक स्व-प्रबंधन से है। बूकचिन ने स्वतंत्र शहरों, क़स्बों और बस्तियों के विचार का समर्थन किया जो खुली जन-विधानसभाओं द्वारा शासित हों। जो आज़ादी से परिसंघ बनाएँ और संकीर्णता को चुनौती दें, स्वतंत्रता को बढ़ावा दें और एक असल प्रतिरोधी-शक्ति (counter-power) बनाएँ।

उन्होंने Vermont और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरे न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में चली आ रही Town Meeting की परम्परा को अच्छा बताया और बताया कि अमेरिकन क्रांति के पूर्व किस तरह इस इलाक़े की Town Meetings ने धीरे-धीरे रैडिकल और समानतावादी चरित्र अपना लिया था।

सामाजिक पारिस्थितिकी-विद मानते हैं कि एक ओर जहाँ पूँजीवाद और राज्य-सत्ता की संस्थाएँ सामाजिक स्तरीकरण (stratification) और लोगों के बीच फ़र्क़ का फ़ायदा उठाते हैं वहीं वैकल्पिक ढाँचे जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रचे-बसे होते हैं वे आम सामाजिक हितों को आगे बढ़ाकर सामाजिक और पारिस्थितिकीय पुननर्माण की ओर ले जा सकते हैं।

इसी विचार से प्रेरित लोग स. रा. अमेरिका, यूरोप और इनके परे भी कई सामाजिक आंदोलनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जन-विधानसभाओं के ढाँचे लेकर आये हैं जैसे १९७० के दशक के आखिर में नाभिकीय ऊर्जा के खिलाफ़ हुए direct action अभियान से लेकर हाल में हुए वैश्विक न्याय/वैकल्पिक-वैश्वीकरण और ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन।

इन आंदोलनों में एक आज़ाद समाज के विभिन्न तत्वों के बारे में सोचना और उन्हें लागू करने की कोशिशों ने प्रतिभागियों को यथा-स्थिति को चुनौती देने और बदलाव वाले भविष्य की सोच को आगे बढ़ाने में सहायता की है।

सामाजिक पारिस्थितिकी-विदों ने पश्चिमी विचार की 'यूटोपिया' परम्परा का भी नवीकरण करने की कोशिश की है। इन्स्टीट्यूट फ़ॉर सोशल इकलॉजी के सह-संस्थापक Dan Chodorkoff एक 'व्यावहारिक यूटोपिया' की वक़ालत करते हैं जिसमें सामाजिक पारिस्थितिकी की सैद्धांतिक गहन जानकारी और राजनैतिक व्यवहार को ग्रीन बिल्डिंग और शहरी रीडिज़ाइन के उन्नत सिद्धांतों और भोजन उत्पादन, ऊर्जा और अन्य ज़रूरतों के लिए ईको-प्रौद्योगिकी के साथ इस्तेमाल किया जाए।

Permaculture जैसे पारिस्थितिकी डिज़ाइन सिद्धांत जो प्राकृतिक जगत के प्रतिमान (patterns) की बेहतर समझ विकसित करने पर बल देते हैं वे सामाजिक पारिस्थितिकी के इस विचार से मेल खाते हैं कि मनुष्य प्रकृति में ऐसे रचनात्मक तरीक़ों से भाग ले सकता है जो प्रक्रति और मनुष्य दोनों ही के लिए लाभकारी हों और साथ ही वे दोहन और विनाश की ऐतिहासिक विरासतों को पलट सकें।

सामाजिक पारिस्थितिकी की सोच ने कई अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलनों पर गहरा असर डाला है चाहे वे ग्रीन पलिटिक्स के शुरुआती साल हों या यूरोप और कनाडा के शहरों में जन-विधानसभाओं द्वारा स्थानीय सशक्तिकरण के हालिया अभियान।

सामाजिक पारिस्थितिकी-विदों ने दुनिया के कई हिस्सों में greener urban design और बस्तियों के सशक्तिकरण के प्रयासों को प्रभावित किया है। शायद इस प्रभाव का सबसे प्रभावशाली हालिया उदाहरण मध्य-पूर्व के कुर्द इलाक़े के लड़ाकों में देखने को मिलता है जहाँ औपनिवेशिक और राज्यसत्ता द्वारा हाशिए पर धकेले गए विविध जातीयता (ethnicity) वाले लोगों ने दुनिया के सबसे युद्ध-ग्रस्त इलाक़ों में परिसंघीय प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्थाएँ खड़ी की हैं।

लगातार साम्प्रदायिक युद्ध और धार्मिक हिंसा के बावजूद, तुर्की-सीरिया सीमा के पास के कुर्द क़स्बे लैंगिक निष्पक्षता और पारिस्थितिकीय पुननर्माण पर काम कर रहे हैं और यह सामाजिक पारिस्थितिकी और अन्य आलोचनात्मक सामाजिक सोचों (जिनकी जड़ें अनेक प्रकार के सांस्कृतिक दृष्टिकोणों में हैं) के इन पर गहरे प्रभाव के चलते हो रहा है।

अन्य संसाधन :

Bookchin, Murray (1982), The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Palo Alto: Cheshire Books (and later editions).

——— (2015), The Next Revolution: Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy. New York: Verso Books.

Eiglad, Eirik (ed.) (2015), Social Ecology and Social Change. Porsgrunn, Norway: New Compass Press.

Institute for Social Ecology, www.social-ecology.org. New Compass Press, www.new-compass.net.

लेखक परिचय:

ब्रायन टोकर Vermont विश्वविद्यालय में पर्यावरण शास्त्र के व्याख्याता हैं। साथ ही Institute for Social Ecology, Vermont, US के हालिया निदेशक और बोर्ड सदस्य भी हैं। उनकी नवीनतम पुस्तक Toward Climate Justice:Perspectives on the Climate Crisis and Social Change (Revised edition; New Compass Press, 2014) है।

स्वायत्तता (Autonomy)

गुस्तावो एस्तेवा Gustavo Esteva

प्रमुख शब्द: स्वायत्तता, रैडिकल लोकतंत्र, पितृसत्ता, आधुनिकता

स्वायत्तता या Autonomy से आज मतलब कई दृष्टिकोणों, प्रथाओं और पूरे विचारधारात्मक स्पेक्ट्रम पर अलग-अलग स्थानों/बिंदुओं से है, संप्रभु व्यक्तियों के स्व-शासन से लेकर उन असल आंदोलनों से है जो रैडिकल लोकतंत्र को पूँजीवाद, उत्पादन की औद्योगिक रीति, पश्चिमी आधुनिकता और पितृसत्ता के परे एक मुक्तिदायी क्षितिज के रूप में देखते हैं।

तो इस तरह autonomy नहीं बल्कि कई तरह की "autonomies" हैं हक़ीक़त में भी और राजनैतिक परियोजनाओं के तौर पर भी, संगठित करने के मिथकों के तौर पर और क्षितिजों के तौर पर भी यानी जो अभी हुआ नहीं है।

परिणामस्वरूप, इस निबंध से मैं विचार और व्यवहार के दो स्कूल्ज़ को बाहर रख रहा हूँ जो मेरे विचार में प्रभावशाली शासन के असल विकल्प नहीं हैं:

व्यक्तिवादी स्कूल, जिसे कभी-कभी लिबर्टेरीयन (मुक्तिवादी) भी कहा जाता है और इसके स्वयं-प्रेरित unions of egoists (Stirner), जो प्राय: पूँजीवादी छद्म अराजकतावाद (pseudo-anarchism) में काम करते हैं।

समाजवादी स्कूल, लेनिनवादी और तथा-कथित पूँजीवाद विरोधी, स्वायत्तता को राज्य की शक्तियों के प्रभुत्व के ढाँचों में ही लंबवत (vertical) विकेंद्रीकरण तक सीमित कर देते हैं। और इसे समाजवाद की ओर संक्रमण के लिए आवश्यक क़रार दिया जाता है। स्वायत्तता को बहुसंख्य लोगों की स्व-गतिविधि (Negri, Virno) मानने वाले इस स्कूल में आते हैं और वे सभी दृष्टिकोण जो जनसाधारण (masses) से सम्बद्ध हैं, लोगों (people) से नहीं।

आइए हम मुद्दे की जड़ में जाते हैं और ऐसे विकल्पों की बात करते हैं जिनमें असल संभावनाएँ हैं।

Autonomy शब्द बहुत पुराना है। सत्रहवीं सदी में, यूरोप में, इस यूनानी शब्द का अभिप्राय यहूदी लोगों को अपने नियम-क़ायदों से रहने की आज़ादी से भी हो सकता था और कांत (जर्मन दार्शनिक) की 'व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता' (autonomy of the individual will) पर चर्चा से भी हो सकता था। यूरोप में बीसवीं सदी में विचार और व्यवहार के कई स्कूल्ज़ ने इस शब्द का इस्तेमाल अपनी धारणाओं और आकांक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए किया।

बाक़ी दुनिया में, ऐसी कई धारणाएँ, प्रथाएँ और विचार प्राचीन काल से मौजूद रहे हैं जिन्हें आज "autonomic" कहा जाएगा। हालिया चर्चाओं को समझने के लिए, हम तीन शब्दों को समझ कर उनमें फ़र्क़ कर लेते हैं-ontonomy, यानी पारम्परिक अंत:-विकसित (endogenous) मानक जो अभी भी सभी जग़ह चालू हैं, autonomy से अभिप्राय उन प्रक्रियाओं से है जिनसे कोई समूह या समुदाय नए मानकों को अपनाता है, और, heteronomy यानी जब नियम दूसरों (यानी बाहरी तत्वों) द्वारा थोपे जाते हैं।

स्वायत्तता सम्बंधी आंदोलन ontonomy और autonomy सम्बंधी क्षेत्रों को जितना हो सके विस्तृत करने की कोशिश करते हैं।

मुक्तिवादी (emancipatory) सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन से निकले एक नए semantic constellation में कुछ हद तक निम्न तत्व होते हैं:

औपचारिक लोकतंत्र के परे: यूनान जिसने 'democracy' शब्द ईजाद किया और स. रा. अमेरिका जिसने इसे इसका आधुनिक स्वरूप दिया दोनों ही ऐसे समाज थे जहाँ 'दास प्रथा' (slavery) मौजूद थी। पिछले २०० सालों के दौरान, दास प्रथा अपने नरम प्रकार में प्रोत्साहित की गयी या शासन-प्रणालियों में छुपी हुई थी जिसे महान अश्वेत बुद्धिजीवी W.E.B. Dubois ने लोकतांत्रिक तानाशाही (democratic despotism) कहा है। भागीदारी वाला लोकतंत्र लोकतांत्रिक समाजों

की verticality (यानी शक्ति के लंबवत स्तरों का होना) को नहीं मिटा पाता, यह वस्तुत: पेशेवर तानाशाही होती है जिसमें पेशेवर हर क्षेत्र में यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ ग्रहण करते हैं और आम लोगों की सरकार के काम-काज में भागीदारी को रोकते हैं।

आज लोकतंत्र से मोहभंग पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। १९९४ में ज़ापातीस्ता के शंख-नाद ने स्वायत्तता को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया। २००१ में आर्जेंटीना के लोगों ने कहा 'अब बस! इन सभी लोगों को जाना होगा!' स्पेन के Indignados ने कहा -'मेरे सपने तुम्हारी मत-पेटी में नहीं समाते'। Occupy Wall Street ने USA में लाखों लोगों को यह मानने के लिए तैयार किया कि उनकी व्यवस्था १ प्रतिशत लोगों की सेवा में लगी हुई है। अभी भी इसे सुधारने की कोशिशें हो रही हैं लेकिन बहुत से संघर्ष इसके बजाय ऐसी जगहों को विस्तृत करने, मज़बूत करने और गहरा करने की कोशिश करते हैं जहाँ लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल स्वयं कर सकें।

वे लोकतंत्र को इसकी निंव से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ आम लोग Leviathan की शक्तियाँ ग्रहण कर सकें, बोलने, अपनी पसंद और उसी के अनुसार काम करने की आज़ादी हासिल कर सकें (Lummis, 1996)। इस तरह के असंख्य प्रयास दुनिया भर में हो रहे हैं। मसलन, १ जनवरी २०१७ को मेक्सिको की National Indigenous Congress ने ज़ापातीस्ता के सहयोग से एक Council of Government के प्रस्ताव को रखा जो मूलवासी और ग़ैर-मूलवासी दोनों ही स्वायत्तताओं पर आधारित हो।

राज्य-सत्ता की वह मशीनरी जिसे नियंत्रण और प्रभुत्व क़ायम करने के उद्देश्य से बनाया गया और काम में लिया जा रहा है उसे अपने क़ब्ज़े में करने के बजाय वे इसे छिन्न-भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे संस्थान बना रहे हैं जहाँ आदेश से आज्ञा-पालन (commanding by obeying) की प्रथा फल-फूल सके।

आर्थिक समाज के परे: स्वायत्तता आंदोलन जो लैटिन अमेरिका में काफ़ी देखने को मिलते हैं वे ना सिर्फ़ नव-उदारवादी वैश्वीकरण को चुनौती दे रहे हैं बल्कि वे बिना समाजवादी हुए पूँजीवाद के भी खिलाफ़ काम कर रहे हैं।

इनमें से कुछ ना सिर्फ़ बाज़ार या राज्य-सत्ता पर अपनी निर्भरता ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि 'अभाव का सिद्धांत' (premise of scarcity) जो आर्थिक समाज को परिभाषित करता है उससे भी नाता तोड़ रहे हैं। तार्किक धारणा यह है कि मानव आकांक्षाएँ तो बहुत ज़्यादा हैं जबकि उसके पास साधन सीमित हैं। ऐसी धारणा एक बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी कर देती है. या तो बाज़ार के ज़रिए या नियोजन द्वारा संसाधनों का बँटवारा। ये आंदोलन, इसके विपरीत, 'पर्याप्तता का सिद्धांत' अपनाते हैं और इस तरह राजनैतिक और आथक दोनों ही मायनों में साधन और साध्य के बीच फ़र्क़ को मिटा देते हैं। इनके संघर्ष उनके उन बदलावों का आकार ले लेते हैं जो वे हासिल करना चाहते हैं।

पश्चिमी आधुनिकता के परे: अधिकाधिक लोग अपने-आप को उन मूल्यों और सत्यों से दूर कर रहे हैं जो पश्चिमी आधुनिकता को परिभाषित करते हैं और जिनमें उन्होंने विश्वास किया था। इनमें से अधिकतर लोग अभी तक एक नया संदर्भ नहीं ढूँढ पाए हैं।

मूल्यों के पतन और दिशाहीन होने की स्थिति में इनमें से कुछ कट्टरपंथी बन सकते हैं। लेक़िन दूसरे शायद उनके पिछले सत्यों की सापेक्षता को मानकर अपने आप को रैडिकल बहुलता-वाद (pluralism) में झोंक सकते हैं और जानने और दुनिया को समझने के नए तरीक़े अपना सकते हैं और दबाए गए ज्ञान के पुनरुत्थान में भाग ले सकते हैं।

Raimon Pannikar से प्रेरित होकर वे उन संज्ञाओं को छोड़कर जो निर्भरता बढ़ाती हैं जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, आदि; उन्हें क्रियाओं के साथ बदल देते हैं जैसे – सीखना, उपचार करना, खाना, रहना आदि और अपनी स्वायत्तता और agency वापस ले लेते हैं। वे मानते हैं कि 'individual' की अवधारणा एक आधुनिक रचना है जिससे वे अपने-आप को दूर कर लेना चाहते हैं और इसके बजाय उस समझ को मानते हैं जिसमें व्यक्ति रिश्तों के जाल में गाँठों की तरह (knots in nets of relationships) होते हैं और एक कृत्रिम 'I/मैं' के बजाय कई प्रकार के वास्तविक 'We/हम' मिलकर एक नया समाज परिभाषित करते हैं।

पितृसत्ता के परे: कई नारीवादी स्कूल्ज़ ऐसे स्वायत्तता आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं जो पारम्परिक उत्तर-पितृसत्तात्मक (post-patriarchal) समाज की सोच से परे जाते हैं। एक स्पष्ट उदाहरण ज़ापातीस्ता समाज है

जहाँ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि राजनीति और नैतिकता सामाजिक जीवन के केंद्र में है और जीवन, महिलाओं और धरती माता की क़द्र करने और उनका ख़याल रखने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

इन समाजों में, स्वायत्त प्रथाएँ रोज़मर्रा के जीवन के सभी पहलुओं में देखने को मिलती हैं, यहाँ शासन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से होता है जो लोगों को समुदाय के तौर पर साथ लाकर आशा और गरिमा पैदा करता हैं।

अन्य संसाधन :

Albertani, Claudio, Guiomar Rovira and Massimo Modonesi (Coord.) (2009), La autonomía possible: Reinvención de la política y emancipación. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Dinerstein, Ana Cecilia (2015), The Politics of Autonomy in Latin America: The Art of Organising Hope. Hampshire, England: Palgrave MacMillan.

Enlace Zapatista, http://enlacezapatista.ezln.org.mx.

Linebaugh, Peter (2006), The Magna Carta Manifesto. Berkeley: University of California Press.

Lummis, Douglas (1996), Radical Democracy. Ithaca: Cornell University Press.

Pannikar, Raimon (1999), El espiritu de la politica. Barcelona: Peninsula.

लेखक परिचय:

गुस्तावो एस्तेवा एक सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी हैं। वे La Jornada और कभी-कभी द गार्डीयन में स्तम्भ लिखते हैं। वे कई स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ज़मीनी जन-संगठनों में भाग लेते रहते हैं और कई किताबें और निबंध लिख चुके हैं।

कुर्दिस्तान की लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था

अज़ीज़ असलान और बेंगी अक़बूलत Azize Aslan & Bengi Akbulut

प्रमुख शब्द: लोकतंत्र, पारिस्थितिकी, लैंगिक आज़ादी, ज़रूरतें

कुर्दिश आंदोलन की वह धारा जो Abdullah Öcalan द्वारा विकसित विचारधारा से प्रभावित है और जिसकी शुरुआत PKK (कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी) की स्थापना के साथ १९७८ में हुई, वह एक स्वतंत्र कुर्दिश राज्य के अपने शुरुआती घोषित उद्देश्य से दूर हट गयी है और अब लोकतांत्रिक परिसंघवाद (Democratic Confederalism) और लोकतांत्रिक स्वायत्तता को अपने प्राथमिक संगठनात्मक मॉडल के तौर पर मानती है।

लोकतांत्रिक स्वायत्तता की मुहिम का मतलब है विभिन्न क्षेत्रों में संगठन की प्रक्रिया जैसे क़ानून, आत्म-रक्षा, कूटनीति, संस्कृति और पारिस्थितिकी।

एक सामुदायिक और 'लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था' बनाना भी इसमें शामिल है जो लैंगिक आज़ादी और पारिस्थितिकी के सिद्धांतों पर आधारित हो। यह मुहिम अर्थव्यवस्था को सामाजिक प्रक्रियाओं में पुनर्स्थापित करती है जिससे सामाजिक प्रजनन के साधन सभी को मिल सकें- एक ऐसी पुनर्रचना जो ज़रूरतों द्वारा परिभाषित हो।

कुर्दिश मुहिम का प्रमुख बौद्धिक आधार Abdullah Öcalan का पूँजीवादी आधुनिकता पर लिखा आलोचनात्मक लेखन है। Öcalan पूँजीवाद के मार्क्सिस्ट विश्लेषण को और गहरा करते हुए औद्योगिक/संग्रह-वादी पूँजीवाद की सार्वभौमिकता को परखते हैं।

यह मुहिम मरी बूकचिन के सामाजिक पारिस्थितिकी और 'मुक्तिवादी नगरपालिका-वाद' (libertarian municipalism) सम्बंधी विचारों से भी प्रेरित है। इन बौद्धिक आधारों की नींव पर लोकतंत्र, लैंगिक आज़ादी और पारिस्थितिकी वे सिद्धांत माने गए हैं जिन पर सभी आर्थिक सम्बंध टिके होने चाहिएँ।

लोकतंत्र का मतलब होता है कि क्या उत्पादन करना है, क्या बाँटना है, संसाधनों का कैसे प्रबंधन और वितरण करना है ये निर्णय भागीदारी और बराबरी से लिए जाएँ।

सामाजिक निर्णय-प्रक्रिया के साधनों में अलग-अलग स्तर और काम के मुताबिक़ communes और councils (परिषद) शामिल हैं- जैसे मोहल्ला, क़स्बा, शहर; युवा, महिला, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी आदि। और साथ ही ऊर्जा सहकारी संस्थाएँ और जल परिषद भी हैं।

लैंगिक आज़ादी/मुक्ति का प्रयास महिलाओं के उस असंबद्ध (discursive) और भौतिक दमन का द्योतक है जो उनके श्रम और ज्ञान की बेक़द्री करता है और इसे अदृश्य बनाता है। और इसका मतलब यह है कि आर्थिक सम्बन्धों को इस प्रकार बनाया जाए कि सभी निर्णय-प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो।

पारिस्थितिकी इस बात पर ज़ोर देती है कि प्राकृतिक जगत मानव और ग़ैर-मानव सभी की सम्मिलित विरासत है और सारी आर्थिक गतिविधियाँ पारिस्थितिकी और समाज दोनों के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होनी चाहिएँ।

एक लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था ऐसी अ-संग्रहवादी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ गतिविधियाँ आर्थिक विकास की एक निर्विवाद ज़रूरत के पीछे नहीं भागती बल्कि सभी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रयास करती है।

इसका मतलब है कि किसी वस्तु/संसाधन की उपयोगिता का मूल्य ज़्यादा होता है, उसके विनिमय का नहीं; भूमि, जल और अन्य स्थानीय संसाधनों पर सबका सामूहिक और बराबर हक़ होता है और ग़ैर-मानवीय प्रकृति को एक वस्तु की तरह नहीं बल्कि सभी सजीव प्राणियों की एक साझा विरासत के रूप में देखा जाता है।

सामाजिक प्रजनन के साधनों पर सामूहिक और बराबर हक़ कार्य-कुशलता या मुनाफ़ा बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस सोच से जुड़े कुछ ठोस प्रस्ताव हैं - भूमि अधिकारों में न्याय, कृषि उत्पादन को ज़रूरत के हिसाब से पुनर्संगठित करना, महिलाओं के अवैतनिक श्रम और जिम्मेदारियों को डे-केयर केंद्र और सामूहिक रसोईयाँ बनाकर बाँटा जाए और ऊर्जा सहकारों और जल परिषदों के ज़रिए संसाधनों का स्थानीय स्व-प्रबंधन किया जाए।

इस मुहिम को संचालित करने के लिए उठाए गए क़दमों में एक अहम उदाहरण भूमिहीन परिवारों को भूमि देने की नगरपालिका की पहल है। शहरों की परिधि में ज़मीन के प्लॉट भूमिहीन परिवारों द्वारा सामूहिक रूप से खेती करने के लिए खोल दिए गए हैं (एक प्लट में १० से ४० परिवारों तक) और इन्हें तकनीकी और उपकरणों सम्बंधी सहयोग भी दिया जा रहा है।

ये प्लॉट (भू-खंड) बीज/पौध भंडारों से जुड़े हुए हैं जहाँ देसी रूप से विकसित बीजों का संरक्षण किया जाता है। यूँ तो इन इकाइयों में उत्पादन मुख्यत: आजीविका चलाने के उद्देश्य से ही होता है पर इन्हें शहरों में स्थित प्रत्यक्ष उत्पादक-उपभोक्ता भंडारों से भी जोड़ा गया है ताकि अतिरिक्त उत्पादन को वहाँ बेचा जा सके।

एक और उदाहरण महिलाओं के सहकारों का नेट्वर्क है जिन्हें कुर्दिश महिला आंदोलन ने आगे बढ़ाया। उत्पादन और वितरण से जुड़े ये सहकार प्राथमिक तौर पर एग्रो-प्रॉसेसिंग और कपड़ा-उत्पादन में संलग्न हैं और वे अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को अपने सहकारी वितरण भंडार Eko-Jin के ज़रिए बेचते हैं।

अधिकतर एग्रो-प्रॉसेसिंग सहकार पहले से मौजूद शहरी कृषि समूहों से निकले होते हैं और उनसे जुड़े होते हैं। ये सहकार फिर नगरपालिका कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अकादमिक लोगों और नागरिक समाज के अन्य लोगों के एक नेट्वर्क का हिस्सा होते हैं जो महिला आंदोलन के बैनर तले बने Free Women's Congress (KJA) से जुड़े होते हैं। KJA वाद-विवाद और निर्णय लेने का स्थान होता है।

लोकतांत्रिक स्वायत्तता की यह मुहिम एक आत्म-निर्भर स्वायत्त अर्थव्यवस्था के संचालन को राजनीतिक स्वायत्तता के एक अपरिहार्य पहलू के तौर पर देखती है। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को सामुदायिक तौर पर संचालित कर राज्य-सत्ता के इस क्षेत्र में दख़ल को पहले ही रोक देना चाहती है।

इस अर्थ में यह मुहिम ज़ापातीस्ता जैसे अन्य स्वायत्तता आंदोलनों जैसी ही है। यह solidarity economy के दुनिया भर में आंदोलनों से भी मेल खाती है क्यूँकि यह पूँजीवादी विकास की अपरिहार्यता को deconstruct करती है और स्व-प्रबंधन, सामाजिक न्याय और पारिस्थितिकीय संरक्षण को प्राथमिकता देती है।

हालाँकि यह देखने की बात है कि लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की यह मुहिम कैसे और मज़बूत बनती है लेकिन कई चुनौतियाँ भी दिखा देती हैं। पहले से मौजूद असमानता (जैसे ज़मीन के मालिकाना हक़ में) अर्थव्यवस्था को सामूहिक और बराबरी से सभी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए संचालित करने में चुनौती बन सकती है।

सभी की ज़रूरतें पूरी करने के सिद्धांत पर चलना और लोकतांत्रिक स्वायत्तता के अ-संग्रहवादी दृष्टिकोण के बीच खींच-तान भी एक चुनौती है।

हालाँकि 'ज़रूरत' का मतलब क्या है इस पर विचार लोकतांत्रिक तरीक़े से किया जाना चाहिए लेकिन सवाल यह भी है कि अपनी ज़रूरत के परे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना अतिरिक्त 'संग्रह' किया जाए और क्या इन ज़रूरतों को सामूहिक रूप से वैध माना जाए। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्की राज्य सत्ता द्वारा सैन्य और राजनीतिक हिंसा में बढ़ोतरी और पूँजीवादी सम्बन्धों का इलाक़े में गहरा फैलाव अहम चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं।

फिर भी, इस मुहिम को जिसने मुमक़िन बनाया और अभी भी इसे आगे बढ़ा रही है वह है कुदश लोगों की एकजुटता के नेट्वर्क। सामूहिकता, बाँटना और एकजुटता हमेशा ही से मज़बूत सांस्कृतिक धागे रहे हैं, संघर्ष के सामूहिक इतिहास ने इन नेट्वर्क़्स को एक सूत्र में पिरोया है। इन्हीं नेट्वर्क़्स के बल पर एक स्वायत्त लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था बनाना मुमक़िन हो पाया। इस अर्थ में, कुर्दिश लोगों की प्रतिबद्धता और एकजुटता-आधारित संगठन एक अमूल्य अवसर है।

अन्य संसाधन :

Akbulut, Bengi (2017), 'Commons against the Tide: The Project of Democratic Economy', in Fikret Adaman, Bengi Akbulut and Murat Arsel (eds), Neoliberal Turkey and Its Discontents: Economic Policy and the Environment under Erdoğan. London: IBTauris.

Aslan, Azize (2016), 'Demokratiközerklikteekonomiközyönetim: Bakûrörneği', Birikim. 325 (May): 93–8; [Economic self-governance in democratic

autonomy: The example of Bakûr (Turkish Kurdistan)], https://cooperativeeconomy.info/economic-self-governance-in-democratic-autonomy-the-example-of-bakur/.

Cooperative Economy, https://cooperativeeconomy.info.

Madra, Yahya M. (2016). 'Democratic Economy Conference: An Introductory Note'. South Atlantic Quarterly. 115: 211–22.

Öcalan, Abdullah (2015), Manifesto for a Democratic Civilization, volume I: Civilization: The Age of Masked Gods and Disguised Kings. Porsgrunn: New Compass Press.

लेखक परिचय:

अज़ीज़ असलान Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto के De Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego में शोध छात्रा हैं। वे ज़ापातीस्ता और कुर्दिश आंदोलनों के एक तुलनात्मक अध्ययन पर काम कर रही हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाई है और इस मुद्दे पर बहुत लेखन भी किया है।

बेंगी अक़बूलत अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर चुकी हैं और कनाडा के Concordia विश्वविद्यालय के भूगोल, पर्यावरण और योजना विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर हैं। वे विकास की राजनैतिक अर्थव्यवस्था, राजनैतिक पारिस्थितिकी, शामलात/लोक-सम्पत्ति और वैकल्पिक अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर काम करती हैं।

ईको–अराजकतावाद (Eco-Anarchism)

टेड ट्रेनर Ted Trainer

प्रमुख शब्द: वृद्धि की सीमाएँ, सादगी, समुदाय की सततता (sustainability), ईको-अराजकतावाद

'विकास' की पारम्परिक परिभाषा के तौर पर वृद्धि (बढ़त) और समृद्धि के लिए अन्त हीन प्रयास करना अवश्यंभावी रूप से पारिस्थितिकीय विनाश करता भी है और इसकी गति भी तेज़ करता है। साथ ही यह असमानता, ग़रीबी, सामाजिक पतन और संसाधनों और बाज़ारों पर नियंत्रण के लिए सैन्य संघर्ष की ओर भी ले जाता है।

जैसा कि Abandon Affluence! (ट्रेनर, १९८५) में कहा गया था इस सम्भावित घातक मुश्किल से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम यह पहचानें कि विकास का प्रभावी सिद्धांत कितना ग़लत और निर्मम है और इसे उस सोच में बदलें जिसे ऑस्ट्रेलिया में हम 'The Simpler Way' कहते हैं।

वैश्विक स्थिति पर यह दृष्टिकोण उस अनपहचाने तथ्य पर ध्यान देता है कि एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के अमीर इलाक़ों में संसाधनों की प्रति व्यक्ति खपत को इसके वर्तमान स्तर से घटाकर १० प्रतिशत पर लाना होगा।

'वृद्धि की सीमा' के इस बुनियादी तर्क को वेब साइट पर विस्तार से बताया गया है।[१] यह विश्लेषण अब बहुत सशक्त हो गया है और इसके विकास के साधनों और साध्य पर अत्यधिक और अपरिहार्य प्रभाव हैं।

चाहे अमीर देश हों या ग़रीब, उनका लक्ष्य छोटी बस्तियाँ होना चाहिए जो आत्म-निर्भर हों, स्व-शासित हों और सादगी, किफ़ायत और जीवन में संतुष्टि के ग़ैर-भौतिक स्त्रोतों की संस्कृति से प्रेरित हों। सिर्फ़ इसी तरह के समुदाय प्रति व्यक्ति संसाधन खपत को पर्याप्त तौर पर नीचे लाकर दुनिया भर के लोगों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन सम्भव बना सकते हैं।

जो तथ्य अक़्सर नज़रंदाज़ कर दिया जाता है वह यह है कि ऐसे इंतज़ामों का ईको-अराजकतावादी होना ज़रूरी है। सिर्फ़ बेहतर भागीदारी वाले स्व-शासित समुदाय ही छोटे स्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को अच्छे से चला सकते हैं। कुछ केंद्रिकृत और राज्य-स्तरीय व्यवस्थाओं की ज़रूरत भी बनी रहेगी लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इसके वर्तमान उत्पादन, व्यापार और GDP का मात्र एक अंश रह जाएगा।

यह अर्थव्यवस्था 'ज़ीरो-वृद्धि' वाली होगी और इसका काम क़स्बों और इलाक़ों को छोटी मात्राओं में बुनियादी चीज़ें जैसे सिमेंट, सिंचाई के लिए पाइप और हल्की मशीनें आदि उपलब्ध कराना होगा। नागरिक पहलों (citizen initiatives) के ज़रिए समुदाय अपने मसलों को ख़ुद नियंत्रित करेंगे तथा अधिकारियों और नौकरशाही पर निर्भरता बहुत कम होगी।

यहाँ स्वयमसेवी नागरिक समितियाँ होंगी, working bees, अनौपचारिक चर्चा, शामलात/लोक-सम्पत्ति, सहज काम और क़स्बा सभाएँ भी होंगी। कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं होंगे जिनसे केंद्रिकृत राज्य स्थानीय व्यवस्थाओं को चला सके।

अहम बात है कि नौकरशाहियों के पास ना तो स्थानीय ज्ञान होता है और ना ज़मीनी स्तर पर ऊर्जा या वह एक साथ जुटने की योग्यता जिससे व्यापक बदलाव लाए जा सकें। जब तक राजनीतिक प्रक्रियाएँ बेहतर भागीदारी वाली ना हों, सशक्तिकरण, एकजुटता और सही निर्णय और कार्रवाई नहीं हो पाएगी।

सबसे अहम, वास्तविक विकास सम्पन्नता के पीछे भागने से नहीं हो सकता; जीवन संतुष्टि के ग़ैर-भौतिक स्त्रोत जब तक व्यक्तिवादी और ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की होड़ की जगह नहीं ले लेते तब तक यह नहीं हो सकता। इसकी अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता होना बहुत ज़रूरी है ताकि किसान और आदिवासी समाज सम्पन्नता को सिर्फ़ आर्थिक वृद्धि से जोड़ कर देखे जाने से बच सकें।

और यह पारम्परिक संस्कृतियों के संरक्षण और उनका जश्न मनाने को पश्चिमी उपभोक्तावाद के आक्रमण से बचाने में अहम योगदान दे सकता है। अमीर दुनिया द्वारा प्रगति करने के बावजूद स्वत:प्रेरित सादगी (Voluntary

Simplicity), Eco-Village, Downshifting, Transition Towns और ईको-अराजकतावादी क्रांति का नेतृत्व किसान और आदिवासी लोग ही करेंगे।

यह ज़रूरी है कि इस विकल्प को किसी तरह तथाकथित बेहतर उपभोक्ता-पूँजीवाद के रास्ते से कमतर या सिर्फ़ सांत्वनादायक ना माना जाए। दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग पहले से ही कमोबेश इस रास्ते पर चल पड़े हैं जैसे La Via Campesina, Chikukwa और Zapatista आंदोलनों में।

सामाजिक उद्देश्यों की एक विशेष दृष्टि पर ज़ोर देने के साथ-साथ The Simpler Way का सीधा प्रभाव साधनों पर भी है। एक बार मानक 'ईको-समाजवादी' संक्रमण सिद्धांत को परखने के बाद यह बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि रणनीति को ईको-अराजकतावादी ही होना होगा।

ईको-समाजवादी इसलिए राज्य सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि वे पूँजीवादी व्यवस्था के (ख़त्म होने के) बाद राजनैतिक केंद्र से व्यवस्था चला सकें। जिन विकल्पों पर हमने ऊपर चर्चा की है वे इन्हें नहीं अपनाना चाहते। उनका इरादा 'औद्योगिक तंत्र को पूँजीवाद के विरोधाभास से मुक्त करना है ताकि सभी के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके'।

ईको-अराजकतावादी रणनीति ज़मीनी एजेन्सी और सांस्कृतिक क्रांति को तवज्जो देती है जहाँ साधारण लोग वैकल्पिक विचार, मूल्यों और व्यवस्थाओं को अपनाएँ। जैसा कि क्रोपोटकिन और तोलस्टोय ने महसूस किया - ''राज्य सत्ता हासिल करना सिर्फ़ वक़्त ज़ाया करना है जब तक कि लोग स्व-शासित और भागीदारी वाले समुदायों की ज़रूरत को पहचानना शुरू ना करें।''

इस दृष्टि और प्रतिबद्धता का उभरना ही असल में क्रांति है और यही आगे के व्यवस्थाओं के परिवर्तन को सम्भव बनाएगा। राज्य सत्ता हासिल करना या उसे ख़त्म करना इसी के ज़रिए हो सकते हैं। The Simpler Way मुहिम[२] की एक अहम चिंता एक व्यावहारिक और विस्तृत योजना प्रदान करना है कि कैसे ईको-अराजकतावादी विकास अमीर और ग़रीब दोनों ही तरह के देशों में हासिल किया जा सकता है।

इसके साथ ही, एक ५३ पृष्ठों की रिपोर्ट[३] बताती है कि कैसे सिड्नी जैसे सम्पन्न शहर के एक उपनगर को संसाधन, पैसा और पारिस्थितिकीय क़ीमत में ९० फ़ीसद कटौती कर बनाया जा सकता है। शहरों के उपनगर, ग्रामीण क़स्बे और तीसरी दुनिया के गाँव सभी स्थानीय संसाधनों और सहकारी इंतज़ामों के ज़रिए अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था से ख़रीदने और उससे होड़ करने के लिए बाध्य होने के बजाय मसला यह है कि सामूहिक जीवन द्वारा कैसे अधिकतम स्वतंत्रता हासिल की जाए।

The Simpler Way की संक्रमण की रणनीति मुख्यतः Transition Towns में काम करने, अ-वृद्धि (De-growth), Permaculture, और ईको-village आंदोलनों पर केंद्रित है। और विशेषतः तीसरी दुनिया के गाँवों में जहाँ बहुत से मॉडल स्थानीय उपाय, सामुदायिक स्व-शासन आदि की कोशिशें हो रही हैं।

नोटः

1. The Limits To Growth Analysis Of Our Global Situation, www.thesimplerway.info/LIMITS.htm.
२. इसकी व्यापक सोच के बारे में जानने के लिए देखें ttp://thesimplerway.info/THEALTERNTIVELong.htm.
3. http://thesimplerway.info/RemakingSettlements.htm.

अन्य संसाधन :

Kropotkin, Peter (1912), Fields, Factories and Workshops. London: Nelson.

Sarkar, Saral (1999), Eco-Socialism or Eco-Capitalism? A Critical Analysis of Humanity's Fundamental Choices. London: Zed Books.

The Simplicity Institute, www.SimplicityInstitute.org.

Trainer, Ted (F.E) (1985), Abandon Affluence! London: Zed Books.

Transition Towns, www.TransitionNetwork.org.

Via Campesina, https://viacampesina.org/en/.

लेखक परिचय:

टेड (ई. एफ़.) ट्रेनर सिड्नी के न्यू साउथ वेल्ज़ विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क से सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं। उन्होंने वैश्विक समस्याओं, सततता से सम्बंधित मुद्दों, अर्थव्यवस्था की रैडिकल आलोचना, वैकल्पिक सामाजिक प्रकारों और उनकी तरफ़ बढ़ने जैसे कई विषयों पर अनेक किताबें और लेख लिखे हैं। वे एक वैकल्पिक जीवनशैली की शिक्षा देने के उद्देश्य से एक वेब साइट बना रहे हैं जिसका नाम है-Pigface Point और आलोचनात्मक वैश्विक शिक्षकों के लिए एक अन्य वेब साइट भी वे बना रहे हैं।

यह प्रकाशन दस निबंधों का संकलन है जो कि मूलतः 'प्लूरीवर्सः एक उत्तर-विकासवादी शब्दकोश' (Pluriverse: A Post-Development Dictionary) नामक पुस्तक से लिए गए हैं । यह दस निबंध तानाशाही और उदार, केंद्रिकृत लोकतंत्र दोनों के बनिस्बत मूलभूत विकल्प पेश करते हैं। इनमें कुछ ज़मीनी पहलें हैं जो बहुत छोटी (स्थानीय) तो कुछ काफ़ी बड़े स्तर की हैं जैसे भारत और लैटिन अमेरिका में मूलवासियों के स्वराज के प्रयास, मेक्सिको के चिआपास में ज़ापातीस्ता और केंद्रीय एशिया में कुर्दिश स्वायत्त क्षेत्र; साथ ही (व्यावहारिक पहलों से जुड़ी हुई) सैद्धांतिक और दूरगामी धारणाएँ जैसे मूलभूत लोकतंत्र, स्वराज, ईको-समाजवाद, ईको-अराजकतावाद आदि भी शामिल हैं।

यह प्रकाशन लोकतंत्र की दिशा पर चल रहे संवाद में एक योगदान है ।

SCHOOL FOR DEMOCRACY SFD
लोकतंत्र शाला

KALPAVRIKSH
कल्पवृक्ष